



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

No. 178]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

विषय : ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पोलीप्रोपीलीन” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच पर निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई ।

सं. 14/5/2009-डीजीएडी.—माननीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के दिनांक 14 मई, 2012 के विविध आदेश सं. एडी/एम/2-4/2012-सीयू (डी बी) के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर 6 जुलाई, 2012 को निर्णयोपरांत सुनवाई की गई थी जिसमें उन हितबद्ध पक्षकारों से भाग लेने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया था ।

2. उक्त सुनवाई के समापन के बाद जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक अनुरोध किए थे, उन्हें पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी । उन्हें तत्पश्चात् उत्तर दायर करने की भी सलाह दी गई थी ।

3. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर संभव समझी गई सीमा तक इस विवरण में विधिवत विचार किया गया है । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है :

मै. सऊदी पोलीलेफिन्स कंपनी, सऊदी अरब, मै. एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब, मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, सऊदी अरब, मै. मरुबेनी कैमिकल एशिया पैसिफिक पी टी ई लि., मै. ओमान पोलीप्रोपीलीन एल एल सी, ओमान, मै. एक्सॉन मोबिल कैमिकल एशिया

पेसिफिक, सिंगापुर, मै. इनाबाटा सिंगापुर, पी टी ई लि., सिंगापुर, मै.सुमितोमो कार्पोरेशन एशिया पी टी ई लि., सिंगापुर की ओर से किए गए लिखित अनुरोध ।

4. इन हितबद्ध पक्षकारों ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

मै. सऊदी पोलीलेफिन्स कंपनी, सऊदी अरब, एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब, सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, सऊदी अरब की ओर से किए गए अनुरोध

- इन प्रतिवादियों ने मुख्यतः अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है और निर्णयोपरांत सुनवाई में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है ।

मै. मरुबेनी कैमिकल एशिया पैसिफिक पी टी ई लि. की ओर से किए गए अनुरोध

- मरुबेनी के परिसर में विस्तृत जांच और सत्यापन करने के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मरुबेनी द्वारा किए गए निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है और इसलिए उसने निर्यातक को शून्य शुल्क प्रदान किया । अर्थात् इसे बख्तरार रखा जाना चाहिए ।
- जांच अवधि के दौरान मरुबेनी की निर्यात कीमत *** अम.डा./मा.ट. थी जबकि याचिकाकर्ता ने सिंगापुर से हुए आयातों के बारे में अपनी याचिका में निर्यात कीमत 1473 अम.डा./मी.ट. होने का दावा किया है । मरुबेनी की निर्यात कीमत और सिंगापुर से आयात कीमत के बीच भारी अंतर से स्वतः यह सिद्ध होता है कि मरुबेनी द्वारा किए गए निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है ।
- याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कीमत कटौती सिंगापुर से औसत आयात कीमत पर आधारित है जो मान्य नहीं है । मरुबेनी ने वर्तमान जांच में पूर्ण सहयोग किया और प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है । यह पाया गया था कि मरुबेनी की निर्यात कीमत याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में दावा की गई औसत निर्यात कीमत से काफी अधिक थी ।
- कि अपने निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन में प्रारंभिक जांच परिणाम की तुलना में अत्यधिक उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है । यह पाटन मार्जिन के निर्धारण में किए गए संशोधन के अनुरूप नहीं है ।
- प्राधिकारी को कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार क्षति मार्जिन का प्रकटन करना चाहिए क्योंकि उनका क्षति मार्जिन नकारात्मक है और इसलिए उनके निर्यातों के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होनी चाहिए । प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन का प्रकटन नहीं किया जिसे प्रकटित किया जाना चाहिए ।

- वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र, समान वस्तु की मौजूदगी, पाटन की मौजूदगी, क्षति की मौजूदगी एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के बारे में अंतिम जांच परिणाम के संबंध में प्राधिकारी से सहमत नहीं हैं।
- मरुबेनी ने अपने ग्राहकों को ब्याजप्रदायी ऋण दिए हैं और ऐसे ब्याज को क्षति माझिन के निर्धारण हेतु आयातों की पड़ुई कीमत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा सूचित सी आई एफ कीमत में ऐसा ब्याज प्रदायी ऋण शामिल नहीं था।

मै. ओमान पोलीप्रोपीलीन एल एल सी, ओमान की ओर से किए गए अनुरोध

- प्रारंभिक जांच की शुरुआत से पूर्व या प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता का मिलान डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से नहीं किया गया था। याचिका की शुरुआत इन्फोझाइव के आंकड़ों के आधार पर की गई थी और प्रारंभिक जांच परिणाम भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए थे जिनके बारे में जांच किए जाने पर प्राधिकारी ने स्वयं त्रुटिपूर्ण पाया था और इन्फोझाइव के आंकड़ों में माप की गलत इकाई का उल्लेख किया गया था। प्राधिकारी ने ओ पी पी के लिए सामान्य मूल्य की गलत गणना की है। ओ पी पी की ओर से दायर प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों में प्राधिकारी द्वारा उत्पादन लागत पर पुनर्विचार करने की जरूरत है तथा डब्ल्यू टी ओ करार के अनुसार आवश्यक समायोजन करने होंगे।
- घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति और आरोपित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि ओमान से हुए आरोपित पाटित आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है और इसे निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है :-

- आवेदक उद्योग की बिक्री संबद्ध वस्तु के आयात से काफी अधिक है और इस बात की संभावना नहीं है कि आयात सूत्रा से घरेलू बिक्री की मात्रा पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है।
- क्षमता उपयोग में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। यह उल्लेख किया गया है कि जांच अवधि में आवेदक घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में जामनगर स्थित उनका संयंत्र बंद होने के कारण मुख्य रूप से गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

- घरेलू बिक्री-मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जो संबद्ध वस्तु की घरेलू मांग में हो रही बढ़ोत्तरी के अनुरूप है। यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 66% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार आवेदक उद्योग पर पाटित आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- समूचे एशिया और विश्व के अन्य भागों में भी उत्पादकों के समक्ष पॉलीप्रोपीलीन कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति पेश आई और इस वजह से जो घाटा हुआ है उसकी वजह पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता है। परिणामतः लाभप्रदता, आर ओ सी ई तथा नकद प्रवाह में गिरावट को संबद्ध देशों से हुए आयातों से नहीं जोड़ा जा सकता और ऐसा विश्व भर में खासकर अप्रैल-दिसंबर, 2008 (जांच अवधि) के दौरान पॉलीप्रोपीलीन की कीमत में आई सामान्य गिरावट के कारण हुआ है।
- संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है और प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की वजह उत्पादकता नहीं है। औसत मालसूची 100(आधार वर्ष 2005-06 में) से घटकर जांच अवधि में 73 हो गई है जिससे बिक्री में सुधार का पता चलता है। वस्तुतः जांच अवधि में मालसूची का स्तर समूची क्षति जांच अवधि के दौरान किसी भी समय विद्यमान स्तर से काफी कम है।

एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पेटिफिक, सिंगापुर की ओर से किए गए अनुरोध

- जांच अवधि का चयन पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार नहीं है। जांच अवधि एक प्रतिनिधिक अवधि होती है जिसके आधार पर इस आशय का निर्धारण किया जाता है कि क्या पाटन और क्षति मौजूद है। वर्तमान मामले में जांच अवधि काफी कम है और इसमें वे महीने शामिल हैं जिनमें वैश्विक मंदी के कारण कच्ची सामग्री तथा पॉलीप्रोपीलीन की कीमत कम रही थी। इस जांच अवधि के दौरान की गई किसी जांच से तथ्यपरक परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि इस अवधि के दौरान पॉलीप्रोपीलीन, नेफ्था और अपरिष्कृत सामग्री की वैश्विक कीमतों में पूर्णतः अप्रत्याशित रूप से घट-बढ़ रही थी। एक्सोन मोबिल का अनुरोध है कि निष्पक्ष और उचित विश्लेषण के लिए जांच अवधि 8 माह की अवधि के लिए तय की जानी चाहिए।

- घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का प्रभाव उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर पड़ा है क्योंकि वे उसी उत्पाद अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन के निर्यात हेतु ब्राजील में पाटनरोधी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। जांच की यह शुरुआत विकास, उद्योग और आंतरिक व्यापार मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई, 2009 के परिपत्र सं. 41 के रूप में प्रकाशित की गई है। क्षति, यदि कोई हो, बाह्य कारणों से हुई है।
- वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि के दौरान पॉलीप्रोपीलीन की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव रहा है और 2008-09 में कीमतों में भारी गिरावट आई है। आर आई एल की कीमत सूची के अनुसार कीमतें 1000 अम.डॉ. प्रति मी.ट. से नीचे चली गई थीं। प्रचलित प्लेट्स कीमतों के साथ तुलना करने पर उक्त कीमत से यह पता चलता है कि आर आई एल की प्रचलित कीमतें प्रचलित बाजार कीमतों के दायरे में थी। इसके विपरीत निर्यातक भारतीय बाजार में क्रेताओं के साथ अपनी दीर्घावधिक संविदा के कारण अधिक कीमत वसूल रहे थे। अतः यह कहना कि घरेलू उद्योग को निर्यातों में हुई वृद्धि के कारण क्षति हुई है, भ्रांतिपूर्ण है और पॉलीप्रोपीलीन व्यापार में वैश्विक स्थिति का उचित प्रदर्शन नहीं है।
- जांच अवधि और परवर्ती दो तिमाहियों के दौरान वैश्विक मांग में वृद्धि हुई तथा पॉलीप्रोपीलीन की कीमत उसकी कीमत के 50% से भी कम हो गई। निर्यात बिक्री की तुलना के अभाव में यह अनुरोध नहीं किया जा सकता कि निर्यात में संभावित कमी या किसी अन्य कारण से संयंत्र बंद किया जाना क्षमता के कम उपयोग का कारण हो सकता है। पेट्रोलियम आधारित उत्पाद होने के कारण पॉलीप्रोपीलीन को विश्व भर में पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमत और प्लास्टिक उद्योग से जोड़ा जाता है। घरेलू उद्योग को खासकर तब वैश्विक बाजार से अलग नहीं किया जा सकता जब घरेलू उद्योग पॉलीप्रोपीलीन की वैश्विक खपत की लगभग 3% मांग की पूर्ति कर रहा है।
- सूचीबद्ध आधार पर पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के कारण कमी से संबंधित दावे को तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका दावा पाटित आयातों के आधार पर किया जाता है। संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल बाजार हिस्से की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयातों के विश्लेषण से यह पता चलेगा कि यह तर्क कोई आधार नहीं रखता है कि संबद्ध देश से हुए आयातों में हुई वृद्धि के कारण लगाई गई पूंजी पर आय 100 के आधार स्तर के मुकाबले घटकर 30 हो गई

है और नक़द प्रवाह के मामले में यह 100 के आधार स्तर के मुकाबले घटकर 48 हो गया है ।

- इस तथ्य के साथ कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में एकाधिकार रखने वाला प्रतिस्पर्धी है, के साथ गोपनीयता का पाटनरोधी शिकायत में दावा कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है ।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आंकड़े और उचित प्रकटन के अभाव में ऐसे आंकड़ों के आधार पर किए गए क्षति के दावे को संबद्ध देशों से हुए आयात के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु विश्वसनीय नहीं माना जा सकता ।
- सितंबर और अक्टूबर, 2008 के बाद स्टॉक समाप्त होने के कारण दावा किया गया घाटा निरर्थक है । उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध प्लेट्स कीमत और घरेलू उद्योग की खुद की कीमतों से यह पता चलता है कि कीमतों में भारी कमी आई है ।
- संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । वस्तुओं समूची क्षति की कल्पना घरेलू उद्योग के लिए संवर्धित क्षति रहित कीमत (एन आई पी) को निर्धारित कर की गई है । उत्पादन लागत अधिक अपनाई गई है । इससे अलावा, क्षति रहित कीमत निकालने के लिए निवेश पर 22% की आय शामिल की गई है । संवर्धित क्षति रहित कीमत तय कर और आयातों के पहुंच मूल्य के साथ ऐसी क्षति रहित कीमत की तुलना करने पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा क्षति निर्धारित की गई है । क्षति के बारे में जांच परिणाम किसी तथ्यात्मक आधार से रहित है ।
- कि प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग के लिए उचित बिक्री कीमत का नियतन निवेश लागू किया गया है । अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को बेहतर स्थिति प्रदान नहीं कर सकता जब कोई पाटन न हुआ हो । अनुरोध है कि कोई लाभ या कोई उचित लाभ जांच अवधि के दौरान उद्योग में वैश्विक लाभ के आधार पर अथवा घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ऐतिहासिक लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उचित विश्लेषण किया जा सके ।
- पिछले दशक में आर आई एल का समूचा कारोबार इतने अधिक आर ओ सी ई (लगाई गई पूंजी पर आय) (22%) को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है । भारत में पी पी कारोबार हेतु वर्ष 2008 में 22% आर ओ सी ई वर्ष 2008 में विद्यमान ऐसी असामान्य आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सर्वथा अवास्तविक होगी क्योंकि उस वर्ष

में (आर आई एल के शब्दों में) "तेल की आसमान छूती हुई कीमतों और खराब मांग" के साथ "वस्तु की कीमत में अघोगामी प्रवृत्ति" देखी गई थी यहां तक कि विश्व के तीनों सबसे बड़े पी पी विनिर्माता भी 22% आर ओ सी ई प्राप्त नहीं कर सके थे जैसा कि वर्ष 2007 और 2008 के उनके समेकित परिणामों से नोट किया जा सकता है । एक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2008 में पी पी उद्योग के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय आर ओ सी ई 1.41% होगी ।

- संवर्धित एन आई पी में संशोधन अपेक्षित है और लाभ का निर्धारण औद्योगिक मापदंडों के आधार पर या लगाई गई पूंजी पर आय के ऐतिहासिक स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए ।
- पॉलीप्रोपीलीन के व्यापार में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति कच्चे तेल की कीमत में अभूतपूर्व अस्थिरता के कारण हुई है न कि भारत में एक्सोनमोबिल द्वारा पॉलीप्रोपीलीन के किसी क्षतिकारी पाटन के कारण । ऐसी वैश्विक प्रवृत्तियों के प्रभाव का कारण संबद्ध आयातों को नहीं माना जा सकता ।
- इस जांच को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त आधार : एक्सोन मोबिल का अनुरोध है कि उसने वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 23 अगस्त, 2010 को जारी अंतिम जांच परिणाम सं. 14/5/2009-डी जी एं डी के खिलाफ माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील 2011 की संख्या 2 दायर की थी । उपर्युक्त जांच परिणाम द्वारा शुल्क की आंशिक वापसी को ध्यान में रखते हुए एक्सोन मोबिल ने उक्त जांच परिणाम के निर्देशन हेतु माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अतिरिक्त आधार देते हुए एक आवेदन भी दायर किया था । एक्सोन मोबिल की अपील का निपटान करते हुए माननीय न्यायाधिकरण (संबंधित मामले में उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले पर पुनः विचार किए जाने के बारे में दिए गए आदेश के आधार पर) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अतिरिक्त आधार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया । माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक्सोनमोबिल द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत अतिरिक्त आधारोंको विचारार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है :
- आवेदकों ने दिनांक 12.1.2012 के अपने पत्र के तहत केन्द्र सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि सऊदी अरब से आयातों पर शुल्क की वापसी को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर पर शुल्क जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 19 के उपबंधों के प्रति भेदभावपूर्ण और प्रतिकूल है । आवेदकों ने अनुरोध

किया है कि उर्पुक्त अधिसूचना द्वारा शुल्क के आंशिक समाहरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपील में पहले से दिए गए आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों को जोड़ने की अनुमति मांगी है ।

- आवेदकों ने अनुरोध किया है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के मद्देनजर शुल्क लगाया जाना प्राधिकारी की सिफारिशों पर आधारित है । क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सऊदी अरब, सिंगापुर और ओमान से हुए आयातों के कारण हुई क्षति का संचयी निर्धारण किया है । यदि सऊदी अरब से हुए आयातों को अलग रखा जाता है तो प्राधिकारी द्वारा क्षति के बारे में निकाला गया जांच परिणाम स्वीकार्य नहीं होगा । इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां प्राधिकारी ने यह माना है कि कई स्रोतों से पाटन हुआ है वहां केन्द्र सरकार के लिए इस बात की छूट है कि वह चुनिंदा/भेदभावपूर्ण आधार पर शुल्क लगाए । इस संबंध में ध्यान केन्द्र सरकार के समक्ष किए गए उनके अनुरोधों की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि -

दिनांक 30 दिसंबर, 2011 को केन्द्र सरकार ने अधिसूचना 130/2011-सी.शु. के तहत सऊदी अरब से हुए आयातों पर लगाए गए शुल्क को वापस ले लिया है । ई एम सी ए पी का विश्वास है कि ऐसा इस कारण से हो सकता है कि केन्द्र सरकार ने यह मन बनाया हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए जांच परिणाम सऊदी अरब के बारे में तथ्यात्मक और विधिसम्मत रूप से स्वीकार्य नहीं हैं । इस संदर्भ में ई एम सी ए पी का अनुरोध है कि सिंगापुर से हुए आयातों के खिलाफ शुल्क निर्दिष्ट प्राधिकारी के उसी जांच परिणाम पर ही आधारित है और इसलिए यदि जांच परिणाम सऊदी अरब के लिए उचित नहीं है तो वे सिंगापुर से हुए आयातों पर शुल्क लगाने के लिए भी समान रूप से अनुचित हैं । इसी तर्ज पर लगाए गए शुल्क को सिंगापुर के खिलाफ भी वापस लिया जाना अपेक्षित है । ई एम सी ए पी का अनुरोध है कि शुल्क लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और यह कि स्थानी विनिर्माता को ऐसे आयातों के कारण परिणामी क्षति हुई है । क्षति से संबंधित पहलू के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारीका समग्र जांच परिणाम सऊदी अरब, सिंगापुर और ओमान से हुए आयातों के प्रभाव के संचयी निर्धारण पर आधारित है ।

अधिनियम और नियमावली में इस वजह से सिफारिशों की आंशिक स्वीकार्यता की अनुमति नहीं है कि नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि जहां एक से अधिक किसी देश से किसी उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच साथ-साथ की जा रही हो, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेगा। यदि सऊदी अरब से हुए आयातों को विश्लेषण से अलग रखा जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की समूची क्षति जांच विधिसम्मत नहीं होगी। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को समग्र रूप में अस्वीकार या स्वीकार किया जा सकता है न कि उसके भाग के रूप में। चूंकि केन्द्र सरकार ने जांच परिणाम को आंशिक रूप से अस्वीकार किया है, इसलिए समूचे जांच परिणाम को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- ई एम सी ए पी ने यह अनुरोध किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोई अलग विश्लेषण नहीं किया है कि क्या सिंगापुर से हुए आयातों का घरेलू उत्पादक पर क्षतिकारी प्रभाव पड़ा है। यदि सऊदी अरब से हुए आयातों को अलग रखा जाता है तो क्षति के संचयी निर्धारण पर आधारित जांच परिणाम स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार सिंगापुर से हुए निर्यातों से हुई क्षति की मौजूदगी की पुष्टि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 ख के अनुसार नहीं की गई है। सिंगापुर से हुए आयातों से घरेलू उत्पादक पर इसके प्रभावों/परिणामी प्रभाव के बारे में किसी जांच परिणाम के अभाव में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता। धारा 9(ख) में यह उपबंध है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 ख के अंतर्ग कोई शुल्क तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि यह निर्धारण न किया गया हो कि ऐसी वस्तु के अयात से भारत में किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या उसका खतरा उत्पन्न हुआ है अथवा उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
- सिंगापुर से हुए आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि क्षति के पहलू के बारे में कोई निर्धारण नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार को इस बात की भी छूट नहीं है कि वह उन देशों के बारे में चुने जाने की नीति का अनुपालन करे जिन्हें उसने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए चुना है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 19 में यह उपबंध है कि शुल्क गैर भेदभाव के आधार पर लगाया जाएगा अर्थात् यह ऐसी वस्तु के सभी आयातों पर लागू होगा भले ही पाटन का स्रोत कोई भी हो। चूंकि केन्द्र सरकार ने सऊदी अरब पर लागू शुल्क को पहले ही वापस ले लिया है, इसलिए सिंगापुर और ओमान से हुए आयातों पर शुल्क जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे देशों पर

शुल्क लगाया जाना नियमावली के नियम 19 के उपबंधों के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके खिलाफ होगा ।

- ई एम सी ए पी ने आगे यह अनुरोध किया है कि उसने भारत में अपने उत्पादों का पाटन नहीं किया है और उसका अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का जांच परिणाम तथ्यों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित है । समूचा जांच परिणाम मंदीकारी ताकतों के समय की अवधि के लिए संकलित आंकड़ों से संबंधित है जब कच्ची सामग्री और तैयार वस्तु की कीमत में भारी अंतर था । ऐसा ऐसी अवधि के चयन के कारण हुआ है जिसमें कृत्रिम मार्जिन निकाला गया है । क्षति विश्लेषण भी दोषपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर से हुए आयातों की पहुंच कीमत उस कीमत से लगभग समान है जिस कीमत पर संगत अवधि के दौरान घरेलू उत्पादक ने वस्तु की बिक्री की है । अतः ई एम सी ए पी द्वारा किए गए निर्यातों का कोई पाटन नहीं हुआ है अथवा परिणामी क्षति नहीं हुई है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र सरकार ने सऊदी अरब पर लागू शुल्क को वापस ले लिया है । ई एम सी ए पी का अनुरोध है कि सिंगापुर के संबंध में शुल्क को जारी रखने का आगे कोई औचित्य नहीं है । अतः ई एम सी ए पी का अनुरोध है कि भारत को हुए उसके निर्यातों के बारे में शुल्क अब वापस ले लिया जाए । आवेदकों का अनुरोध है कि सऊदी अरब से हुए आयातों पर शुल्क वापस लिए जाने के मद्देनजर सिंगापुर के खिलाफ लगाया गया शुल्क पूर्णतः अनुचित और भेदभावपूर्ण है ।

इनाबाटा सिंगापुर पी टी ई लि., सिंगापुर की ओर से लिए गए अनुरोध

- जांच अवधि का चयन पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार नहीं है । जांच अवधि एक प्रतिनिधिक अवधि होती है जिसके आधार पर इस आशय का निर्धारण किया जाता है कि क्या पाटन और क्षति मौजूद है । वर्तमान मामले में जांच अवधि काफी कम है और इसमें वे महीने शामिल हैं जिनमें वैश्विक मंदी के कारण कच्ची सामग्री तथा पॉलीप्रोपीलीन की कीमत कम रही थी । इस जांच अवधि के दौरान की गई किसी जांच से तथ्यपरक परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि इस अवधि के दौरान पॉलीप्रोपीलीन, नेफ्था और अपरिष्कृत सामग्री की वैश्विक कीमतों में पूर्णतः अप्रत्याशित रूप से घट-बढ़ रही थी । कच्ची सामग्री की कीमत में परिवर्तन काफी अधिक हुए थे और परिणामतः कीमत के नियतम हेतु उत्पादन लागत का अनुमान लगाना कठिन था ।

- उनके द्वारा निर्यातित उत्पादों में से एक उत्पाद एक यौगिक है और इसलिए वह जांच के दायरे से बाहर है। आई एस पी एल का अनुरोध है कि यौगिक और पॉलीप्रोपीलीन तकनीक या वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। यौगिक एक तैयार उत्पाद होता है जो किसी खास अनुप्रयोग के लिए सुनिर्धारित होता है और इसमें पॉलीप्रोपीलीन से इतर सामग्री शामिल हो सकती है। जबकि पॉलीप्रोपीलीन को किसी यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उलट संभव नहीं है। अतः जहां पॉलीप्रोपीलीन के विविध अनुप्रयोग होते हैं, वहीं यौगिक का उपयोग केवल ऐसे अनुप्रयोग में किया जा सकता है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है।
- अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह माना है कि चूंकि आई एस पी एल द्वारा किए गए निर्यात वाणिज्यिक मात्राओं में नहीं हैं इसलिए उसके निमित्त कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता। आई एस पी एल का अनुरोध है कि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पाटनरोधी शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के नियम 17 के उपनियम (3) के अनुसार प्राधिकारी के लिए जांचाधीन उत्पाद के संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक हेतु पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। इस संबंध में अनुरोध है कि उक्त नियमावली में नियम 17 के प्रयोजनार्थ कोई भेद नहीं किया गया है।
- उत्पादक और आवेदक के बीच की गई बिक्री घरेलू बिक्री है। आई एस पी एल द्वारा भारत में ग्राहकों को की गई बिक्री निर्यात बिक्री है। टी पी सी ने इन सौदों को घरेलू बिक्री के रूप में सही ढंग से लेखाबद्ध किया है। वस्तुतः प्रश्नावली के उत्तर के प्रयोजनार्थ टी पी सी ने उन घरेलू बिक्रियों को अलग से पहचानने का प्रयास भी किया है जो निर्यात के दौरान की गई हैं। अतः मात्र इस वजह से कि इन सौदों को टी पी सी द्वारा की गई घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाया गया है, दोनों उत्तरों में किसी विसंगति का पता नहीं चलता है।
- भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार ("सीका") का अनुपालन नहीं किया गया है। गैट 1994 के अनुच्छेद vi के अनुबंध-II के पैरा 6 के साथ पठित सीका के अनुच्छेद 2.7.2 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी पर उस स्थिति में सूचना प्राप्त करने के लिए "सर्वोत्तम प्रयास" करने का दायित्व डाला गया है यदि उसका यह विचार है कि आई एस पी एल द्वारा

अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की है। उपर्युक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आई एस पी एल का यह विचार है कि जहां पूर्व में प्रस्तुत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा किए गए नए दावे या लगाए गए आरोप के कारण स्वीकार नहीं की जाती है या उसे अधूरा माना जाता है वहां आई एस पी एल को उक्त नए दावे या आरोप के बारे में उत्तर देने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

- कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि उसी उत्पाद अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन के निर्यात हेतु ब्राजील में वह पाटनरोधी कार्यवाही का सामना कर रहा है। यह सूचना विकास, उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के 23 जुलाई, 2009 के परिपत्र सं. 41 के रूप में प्रकाशित की गई है। क्षति यदि कोई है, वह बाह्य कारकों से हुई है।
- कि यह अनुमान लगाना न्यायोचित नहीं है कि जांच अवधि (वार्षिक) के दौरान हुए 15,17,688 मी.ट. के उत्पादन के मुकाबले घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण कीमत कटौती और निवेश पर आय की वजह से घाटा हुआ है। (घरेलू उद्योग के उत्पादन का 6.83%)।
- कि घरेलू उद्योग ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि भारत में पॉलीप्रोपीलीन का सबसे बड़ा विनिर्माता और विक्रेता होने के कारण घरेलू उद्योग ने हमेशा अपनी एकाधिकारवादी स्थिति का दुरुपयोग किया है कि जांच अवधि के दौरान पॉलीप्रोपीलीन (2008 की तीसरी और चौथी तिमाही) की कीमत वैश्विक कमी का कुल बिक्री पर प्रभाव पड़ सकता है जिसमें घरेलू बिक्री भी शामिल है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि निवेश पर आय, नकद प्रवाह आदि में गिरावट संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण आई है।
- कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने जांच परिणाम में यह बताया है कि घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा 89% से बढ़कर 92% हो गया है। तथापि, यह बताया गया है कि "ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी प्राप्ति की लागत पर बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए ऐसा किया है"। इस संबंध में यह अनुरोध है कि निर्यातक की कीमतें संविदागत कीमतें थीं जिनका निर्धारण पूर्ववर्ती तिमाही/छमाही के लिए प्लेट्स औसत कीमत के आधार पर किया गया था। इस पहलू की पुष्टि सितंबर और नवंबर, 2008 के महीने में इनाबाटा द्वारा किए गए निर्यातों के दोनों सौदों की तुलना द्वारा की जा सकती है जिनमें

लगभग 1000 अम.डॉ. प्रति मी.ट. की प्रचलित कीमत के बावजूद आई एस पी एल ने 2076 अम.डॉ. प्रति मी.ट. की कीमत वसूली है जो आर आई एल की प्रचलित बाजार कीमतों या प्लेट्स कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। अतः यह कहना गलत है कि निर्यातकों ने उच्चतर कीमतें वसूली हैं जबकि घरेलू उद्योग कीमत में वृद्धि नहीं कर सका क्योंकि उच्च कीमतों की वसूली दीर्घावधिक संविदाओं के कारण की गई थी।

- कि घरेलू उद्योग ने न माह की जांच अवधि पर बड़ी चालाकी से चयन किया है और वह दिसंबर, 2008 से आगे नहीं गया है क्योंकि 2008 की अंतिम तिमाही में पॉलीप्रोपीलीन की वैश्विक कीमत में गिरावट आई थी। कीमत में यह गिरावट 50% से अधिक हुई थी जिसकी वजह से विश्व भर में मांग में कम आने के कारण वैश्विक उद्योग को घाटा हुआ था। जांच अवधि के दौरान आयातों में हुई किसी वृद्धि से आधार वर्ष 2005-06 की तुलना में आई एस पी एल को 100 की तुलना में 20 का घाटा नहीं हो सकता। घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयातों में 10% (लगभग) की कमी के कारण 80% तक लाभ में हुए घाटे का आरोप लगाकर एक नई आर्थिक कहानी गढ़ रहा है।
- कि जांच अवधि तथा परवर्ती दो तिमाहियों में वैश्विक मांग में गिरावट आई है और पॉलीप्रोपीलीन की कीमत में उसके ग्रेड के 50% से भी अधिक कमी आई है। निर्यात बिक्री की तुलना के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि निर्यात में संभावित गिरावट या किसी अन्य कारण से संयंत्र बंद किए जाने की वजह से क्षमता का कम उपयोग हो सकता है। पेट्रोलियम आधारित उत्पाद होने के कारण पॉलीप्रोपीलीन को विश्व भर में पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमत और प्लास्टिक उद्योग से जोड़ा जाता है। घरेलू उद्योग को खासकर तब वैश्विक बाजार से अलग नहीं किया जा सकता जब घरेलू उद्योग पॉलीप्रोपीलीन की वैश्विक खपत की लगभग 3% मांग की पूर्ति कर रहा है।
- कि संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल बाजार हिस्से की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयातों के विश्लेषण के समय यह पता चलेगा कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि लगाई गई पूंजी पर आय संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण 100 के आधार स्तर से घटकर 30 के स्तर पर पहुंच गई है और नुकद प्रवाह के मामले में यह 100 के आधार के मुकाबले घटकर 48 हो गई है।

- गोपनीयता के दावे के साथ-साथ यह तथ्य कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धी है, पाटनरोधी शिकायत करने के लिए कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है ।
- कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और उचित प्रकटन के अभाव में ऐसे आंकड़ों के अभाव में किए गए क्षति के दावे को संबद्ध देशों से आयात के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए भरोसेमंद नहीं माना जा सकता ।
- कि सितंबर, और अक्टूबर, 2008 के बाद स्टॉक समाप्त होने के कारण दावा किया गया घाटा निराधार है । उल्लिखित वेबसाइट पर प्लेट्स कीमतों और घरेलू उद्योग की खुद की कीमतों से स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि कीमतों पर भारी गिरावट आई है ।
- इस बात की प्रबल संभावना है कि पालीप्रोपीलीन के कारोबार में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति कच्चे तेल की कीमत में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव के कारण हुई है न कि भारत में आई एस पी एल द्वारा पॉलीप्रोपीलीन के किसी क्षतिकारी पाटन के कारण । ऐसी वैश्विक प्रवृत्ति के प्रभाव का कारण संबद्ध आयातों को नहीं माना जा सकता ।

सुमितोमो कारपोरेशन एशिया पी टी ई लि., सिंगापुर की ओर से किए गए अनुरोध

- कि जांच अवधि का चयन पाटनरोधी व्यवहार संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार नहीं है । जांच अवधि एक प्रतिनिधिक अवधि होती है जिसके आधार पर इस आशय का निर्धारण किया जाता है कि क्या पाटन और क्षति मौजूद है । वर्तमान मामले में जांच अवधि काफी कम है और इसमें वे महीने शामिल हैं जिनमें वैश्विक मंदी के कारण कच्ची सामग्री तथा पॉलीप्रोपीलीन की कीमत कम रही थी । इस जांच अवधि के दौरान की गई किसी जांच से तथ्यपरक परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि इस अवधि के दौरान पॉलीप्रोपीलीन, नेथ्या और अपरिष्कृत सामग्री की वैश्विक कीमतों में पूर्णतः अप्रत्याशित रूप से घट-बढ़ रही थी । कच्ची सामग्री कीमत में परिवर्तन काफी अधिक था और परिणामतः कीमतों के नियतन हेतु उत्पादन लागत का अनुमान लगाना कठिन था ।
- कि क्षति का संचयी निर्धारण अपेक्षित नहीं है । निर्दिष्ट प्राधिकारी एक से अधिक देश से हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण तभी कर सकता है जब वह यह निर्धारित करे कि आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को

देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है । सिंगापुर तथा घरेलू उद्योग की बिक्री के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अन्य देशों (जांचाधीन) की स्थितियों से काफी भिन्न हैं । सिंगापुर से निर्यात जांचाधीन अन्य देशों से हुए आयातों की कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर किए गए थे । अतः अन्य देशों की तुलना में सिंगापुर के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां काफी भिन्न हैं । इसका तात्पर्य यह है कि सिंगापुर के लिए क्षति का पृथक निर्धारण किया जाना चाहिए । इसके अलावा, चूंकि सिंगापुर से हुए आयातों के कारण नगण्य क्षति हुई है, इसलिए जांच को आगे समाप्त कर दिया जाए ।

- कि अंतिम जांच परिणाम में क्षति मापदंडों की जांच निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं है । पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का अभाव है । कि क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट जामनगर स्थित संयंत्र के बंद होने के कारण आई है । घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी है, कम कीमत पर बिक्री नगण्य है । कि अन्य कारकों के कारण लाभप्रदता में गिरावट की वजह से विश्व भर में पेट्रोकेमिकल कंपनियां कठिन दौर से गुजर रही हैं । यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है, क्षति के दावे को नकार देता है । कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट यदि कोई हो, पेट्रोलियम की कीमतों में घट-बढ़ जैसे अन्य कारकों के कारण आई है । ऐसी विकट मंदी के समय नकद प्रवाह में गिरावट सर्वथा प्रचलित है । घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों की अपनी क्षमता में वृद्धि की है और जांच अवधि के दौरान मजदूरी को बढ़ाया है । ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में किसी प्रकार की बाधा आई है ।
- इस बात की प्रबल संभावना है कि पालीप्रोपीलीन के कारोबार में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति कच्चे तेल की कीमत में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव के कारण हुई है न कि भारत में एस सी ए द्वारा पॉलीप्रोपीलीन के किसी क्षतिकारी पाटन के कारण । ऐसी वैश्विक प्रवृत्ति के प्रभाव का कारण संबद्ध आयातों को नहीं माना जा सकता ।

हल्दिया पेट्रोकेमिकल लि. की ओर से किए गए अनुरोध

- कि निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता को निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वीकार्य मानदंड, कानून और व्यापार सूचनाओं का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए गलत ढंग से स्वीकार किया है ।
- कि असंगतपूर्ण तुलना करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम में उत्पादक के सामान्य मूल्य और निर्यातक के निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए पाटन

मार्जिन की गणना की है । अनुरोध है कि ऐसी किसी नीति का प्रावधान भारतीय पाटनरोधी कानून में नहीं है ।

- कि ऐसे कुछेक निर्यातकों/उत्पादकों की संलिप्तता बताई गई है जो असहयोगी रहे हैं और परिणामतः उन्हें लाभान्वित किया गया है क्योंकि उन्हें असहयोगी घोषित नहीं किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में इस तथ्य को नोट किया था कि सेबिक जो दो संबद्ध कंपनियों अर्थात् मै. आई बी एन जहीर और मै. यानपेट को संबद्ध वस्तु की बिक्री करती है, ने परिशिष्ट 4-9 के संबंध में कोई ब्योरा प्रदान नहीं किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह भी देखा था कि अपेक्षित सूचना के अभाव में प्राधिकारी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी जांच करने में असमर्थ हैं ।
- कि निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उत्तर दायर करने में किए गए विलंब को माफ नहीं किया जाना चाहिए । पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) में यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर निर्यातकों/विदेशी उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । पर्याप्त कारण दर्शाए जाने के बाद ही निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार की अनुमति दी जा सकती है ।
- कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम में अपनाया गया भेद सही नहीं है । जहां तक वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यौगिक विचाराधीन उत्पाद का भाग हैं, और उन्होंने टर-पॉलीमर को जांच के दायरे और क्षेत्र के भीतर मानने का निर्णय लिया है ।
- कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संपूर्ण और व्यापक निर्धारण नहीं किया है ।
- कि सऊदी अरब, जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, को अलग रखे जाने से घरेलू उद्योग को सतत क्षति का अनिवार्य रूप से सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह खंड जाहिर तौर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शामिल नहीं किया जा रहा है ।
- कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्धन्यायिक प्राधिकारण है और इस प्रकार वह कानून के नियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा बाध्य है । इसमें घरेलू उद्योग को समस्त संगत सूचना प्रदान करने का प्रावधान है और जहां ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसे अप्रकटन को न्यायोचित ठहराने के लिए विस्तृत कारण देने चाहिए ।

हाइड्रो एस एंड एस लि. की ओर से किए गए अनुरोध

- कि वर्तमान मामले में जांच अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक) काफी कम है और उसमें वे महीने शामिल हैं जिनमें वैश्विक मंदी के कारण कच्ची सामग्री तथा पॉलीप्रोपीलीन की कीमतें काफी कम थीं। इसके अलावा, कोरिया, अमरीका और ताइवान से हुए आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई परवर्ती पाटनरोधी जांचों से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग के आर्थिक आंकड़ों से स्वतः वर्तमान मामले में जांच अवधि के तुरंत बाद अल्पावधि में निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- कि नियम 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। घरेलू उद्योग ने उचित प्रक्रिया के सिद्धांत की पूर्ण अनदेखी की है जिसके तहत घरेलू उद्योग अपने हित के अनुसार किसी रूप में अपने आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है जबकि अपने हित के बचाव हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों पर गंभीर चोट पहुंचाई गई है।
- कि संयंत्र का प्रकटन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के परिणाम के रूप में किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने लगाई गई पूंजी के संबंध में कोई सार्थक प्रकटन नहीं किया है जिसका प्रयोग क्षमता संवर्धन के प्रयोजनार्थ किया गया हो। अनुरोध है कि संयंत्र की अवधि का प्रकटन क्षमता संवर्धन के प्रयोजनार्थ किया जाता है न कि पाटन की गणना के लिए। इसके अलावा, जैसा कि जांच परिणाम से स्पष्ट होता है, याचिकाकर्ता का मामला कीमत कटौती की बजाए कम कीमत पर बिक्री पर आधारित है जिससे स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि आयात याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री कीमत से अधिक कीमत पर किए गए थे। इस प्रकार संयंत्र बंद होने के कारण हुई क्षति का दावा स्वीकार्य नहीं है और उसे अस्वीकार किया जाए।
- कि याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा जानबूझकर व्यापक रखी गई है ताकि उसके दायरे को बढ़ाया जा सके और उसमें उन ग्रेडों को भी शामिल किया जा सके जिनका उत्पादन न तो याचिकाकर्ता कंपनी करती है और न ही ऐसे विनिर्देशनों वाली वस्तु का उत्पादन करने की उसके पास क्षमता है।
- क्षति : कि यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है, तथापि संबद्ध देशों से हुए आयातों में भारी गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की बिक्री में मामूली गिरावट आई है। परंतु यह गिरावट याचिकाकर्ता द्वारा संयंत्र बंद किए जाने के कारण आई है। लेकिन समान रूप से उल्लेखनीय तथ्य

यह भी है कि उक्त अवधि के दौरान संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में भी कमी आई है ।

- कि इस अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा समान रहा है जबकि यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना करने पर भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा 90% से बढ़कर 92% हो गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण नहीं हुई है अपितु घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण हुई है ।
- कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता बढ़ाई है । लगभग 4 सप्ताह तक संयंत्र की योजनाबद्ध बंदी के बावजूद याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग उच्च बना रहा है । यह नोट करना प्रासंगिक है कि जांच अवधि (कुल 9 माह) के दौरान एक माह के लिए घरेलू उद्योग ने योजनाबद्ध बंदी का सहारा लिया है । संयंत्र की यह बंदी कुल मांग और घरेलू कुल उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि हेतु की गई थी । अतः योजनाबद्ध बंदी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुआ कोई कारोबारी घाटा केवल घरेलू उद्योग के कृत्य की वजह से हुआ है और आरोपित पाटित वस्तु के आयातों को इसका जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता ।
- कि जहां एक ओर आयातों के पहुंच मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर आयातों में गिरावट आई है, इसलिए क्षति, यदि कोई हो, का कारण आयातों को नहीं माना जा सकता । लाभप्रदता घरेलू उद्योग के उत्पादन के स्थगन के कारण प्रभावित हुई है ।
- कि घरेलू उद्योग ने मजदूरी में वृद्धि की है जिससे लागत बढ़ी है । आगे यह अनुरोध किया जाता है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही प्राधिकारी ने उन कारणों और कारकों का खुलासा नहीं किया है जिनकी वजह से याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है ।
- कि कीमत कटौती के बारे में प्राधिकारी का जांच परिणाम मौन है और उसमें केवल कम कीमत पर बिक्री पर चर्चा की गई है जिसका स्पष्ट आशय यह निकलता है कि कोई कीमत कटौती नहीं हुई है । चूंकि कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है, इसलिए इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि आयातित वस्तु का पहुंच मूल्य याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री कीमत से काफी अधिक था ।

- कि यद्यपि, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है, तथापि, कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है जिससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि कर्मचारियों की मजदूरियों में भारी वृद्धि की गई है जिससे उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- कि याचिकाकर्ता पॉलीप्रोपीलीन के सभी प्रकारों का उत्पादन न होने की बात को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क नियतम संदर्भ कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । याचिकाकर्ता द्वारा किया गया उत्पादन बाधित आपूर्ति और खासकर गुणवत्ता तथा उत्पाद संगतता के दोनों मुद्दों द्वारा प्रभावित हुआ है । इसके अलावा, रूपए के अवमूल्यन से याचिकाकर्ता के लिए संरक्षण स्तर में आगे वृद्धि होगी क्योंकि आयात महंगे हो जाएंगे ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लिखित अनुरोध

5. घरेलू उद्योग की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- इसने आवेदन में पूर्व में किए गए सभी अनुरोधों, टिप्पणियों, अन्य अनुरोधों को दोहराया है और उन पर भरोसा किया है ।
- प्राधिकारी को मै. सेबिक को पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं । यह दोहराया जाता है कि सेबिक को असहयोगी पक्षकार माना जाना चाहिए था ।
- मै. इतोचू को पृथक व्यवहार या पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत को हुए निर्यातों की पूर्ण श्रृंखला से संबंधित सूचना की पुष्टि नहीं की जा सकती । प्राधिकारी ने केवल इस आधार पर निर्यातकों की सूचना को अन्य मामलों में लगातार अस्वीकृत किया है कि वे भारत को हुए निर्यातों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहे हैं ।
- पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के उपबंधों के खिलाफ उत्तर दायर करने में हुए विलंब को माफ कर दिया गया है । प्राधिकारी उत्तर दायर करने का समय तभी बढ़ा सकते हैं जब संबंधित हितबद्ध पक्षकार ने पर्याप्त कारण दर्शाया हो । सार्वजनिक फाइल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मै. सेबिक ने विलंबित उत्तर का कोई कारण नहीं दिया है । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समय बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं

उठता है । इस बात को मानना होगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वयं समय बढ़ाने का न तो कोई कानूनी उपबंध है और न ही ऐसी कोई अनुकूल परिस्थितियां हैं । समय विस्तार हेतु आधार प्रस्तुत करना नियम 6(4) के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी हेतु एक पूर्व शर्त है । चूंकि यह निर्विवादित तथ्य है कि पक्षकार ने कोई कारण नहीं दिया है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्तर दायर करने में हुए इतने अधिक विलंब को माफी नहीं कर सकते ।

- मै. सेबिक ने उन सभी संबंधित कंपनियों के लिए सूचना प्रदान नहीं की थी जो संबद्ध वस्तु का कार्यकलाप कर रही हैं जबकि कानूनी तौर पर उन्हें समस्त संबंधित पक्षकारों के लिए सूचना देना अपेक्षित है । यह निर्विवाद सच है कि मै. सेबिक ने मै. यानसाब यान्हू नेशनल पेट्रोकेमिकल कं. और मै. सऊदी कयान के लिए सूचना दी थी जो स्पष्ट तौर पर संबद्ध वस्तु का कार्यकलाप भी करती हैं । एक मात्र आर्थिक उद्यम और उसकी संबंधित कंपनियों की पूर्ण सूचना के अभाव में उन्हें सहयोगी निर्यातक नहीं माना जा सकता ।
- शुल्क संयोजन नियम 17(3) के विरुद्ध है । इस संदर्भ में अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादक के सामान्य मूल्य और निर्यातक की निर्यात कीमत को हिसाब में लेकर पाटन मार्जिन की गणना की है । अनुरोध है कि कानून में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को शुल्क संयोजन निर्धारित करने की अनुमति हो । इसके अलावा, इस कार्य प्रणाली से कभी भी पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता ।
- प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में टर पॉलीमर्स को इस विषय पर किए गए अनुरोधों और निर्धारित कानून तथा प्रक्रिया की जांच किए बिना विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग रखा गया है । हितबद्ध पक्षकारों से तकनीकी विनिर्देशनों, रासायनिक संरचना और तकनीकी प्रतिस्थापनीयता आदि से संबंधित ब्यौरों के अभाव में ऐसा अपवर्जन किसी विधिक औचित्य और आधार से रहित था । इसके अलावा, रिकॉर्ड में यह सिद्ध करने के लिए कोई उचित आधार नहीं रखा गया है कि उक्त पॉलिमर विचाराधीन उत्पाद के समान नहीं है ।
- ऐसे अपवर्जन की मांग को सिद्ध करने का दायित्व ऐसे अपवर्जन का दावा करने वाले पक्षकार पर होता है । सिद्ध करने के ऐसे दायित्व की पूर्ति के बिना यह अपवर्जन कानूनन दोषपूर्ण है । इसके अलावा, अनुरोध है कि घरेलू उद्योग कोई भी ग्रेड उत्पादित करने में सक्षम है और इस प्रकार यह अपवर्जन घरेलू उद्योग के विधिसम्मत दावे की जांच किए बिना प्रदान किया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझने में विफल रहे हैं

कि टर-पॉलीमर को-पॉलिमर का एक भाग है जहां तृतीय मोनोमर 1% से कम होता है और एथिलिन प्रमुख को-मोनोमर बना रहता है ।

मै. एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल कं., सऊदी अरब, मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, सऊदी अरब, मै. मरुबेनी कैमिकल एशिया पेट्रोलियम पी ओ ई लि., मै. एक्सोन मोबिल एशिया पेट्रोलियम, सिंगापुर, मै. इनाबाटा सिंगापुर पी टी ई, सिंगापुर, मै. सुमितोमो कारपोरेशन एशिया पी टी ई लि., सिंगापुर की ओर से किए गए प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध

6. इन हितबद्ध पक्षकारों की ओर से संक्षेप में निम्नलिखित प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध किए गए हैं :-

- कि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क संयोजन को चुनौती दी है, मरुबेनी का अनुरोध है कि इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की पद्धति अब सुनिर्धारित है । घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई तथ्यात्मक आधार नहीं दिया है जिसकी वजह से स्थापित पद्धति पर पुनर्विचार अपेक्षित हो । जांच के स्वरूप और तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में या अन्यथा विधिक या तथ्यात्मक आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही किसी उच्च प्राधिकारी के किसी निर्णय और न ही घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित किसी तथ्यात्मक आधार में कोई परिवर्तन हुआ है । मरुबेनी का अनुरोध है कि इस संबंध में स्थापित पद्धति की समीक्षा करने या उस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है । इसके अलावा, मरुबेनी ने कम कीमत पर कोई निर्यात नहीं किया है और मरुबेनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि होती है कि यह निर्यात कीमत उस कीमत से काफी अधिक है जिस कीमत पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय बाजार में वस्तु की बिक्री की है, इसलिए मरुबेनी का अनुरोध है कि कंपनी को पाटनरोधी शुल्क का दंड नहीं दिया जाना चाहिए । मरुबेनी अन्य व्यापार कंपनियों द्वारा कम कीमत पर किए गए निर्यातों के लिए जिम्मेवार नहीं है और इसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए ।
- कि सहयोगी निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के संबंध में शुल्क संयोजन की सिफारिश करने की प्राधिकारी की पद्धति को डब्ल्यू टी ओ में या भारत में सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई है । इसके अलावा यह अपेक्षित नहीं है कि किसी उत्पादक का पृथक निर्धारण करने के लिए सभी असंबद्ध व्यापारी निर्यातक किसी जांच में सहयोग करें । ऐसी स्थिति में जहां कई उत्पादकों से खरीद करने वाला कोई सहयोगी व्यापारी निर्यातक सहयोग करता है परंतु सभी उत्पादक ऐसा नहीं करते हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए । बहरहाल स्थापित पद्धति में किसी परिवर्तन का उचित तरीका यह होगा कि इसे सार्वजनिक सूचना के जरिए प्रकाशित किया जाए और

संबंधित व्यापार सूचना प्रकाशित किए जाने के बाद शुरू की गई जांच पर इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए ।

- जहां तक घरेलू उद्योग के इस दावे का संबंध है कि मै. सेबिक को असहयोगी निर्यातक माना जाना चाहिए क्योंकि उसने उत्पादन में शामिल सभी संबंधित पक्षकारों के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की है, अनुरोध है कि मै. सेबिक ने ऐसे दो उत्पादकों के लिए उत्तर दायर किया है जिन्होंने उत्पादन पर संबद्ध वस्तु की बिक्री मै. सेबिक को की है । इस सूचना का डी जी ए डी ने सत्यापन भी किया था । इसके अलावा जहां तक इस आरोप का संबंध है कि अन्य संबंधित कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है, यह उल्लेखनीय है कि ऐसे उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया है । अतः दोनों कंपनियों ने पृथक उत्तर दायर नहीं किया । इसे देखते हुए घरेलू उद्योग का दावा बेकार हो जाता है ।
- कि यह तर्क दिया गया है कि शुल्क संयोजन की अवधारण कानून असंगत है । एक्सोन मोबिल का अनुरोध है कि इस अनुरोध का कोई आधार नहीं है क्योंकि नियम 17 के अंतर्गत जांचाधीन उत्पाद के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या संबंधित उत्पादक के लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि “निर्यातक” पद को इस प्रकार परिभाषित नहीं किया गया है जिसका तात्पर्य उस निर्यातक से हो जो उत्पादन करता है; “उत्पादक” पद को इस प्रकार परिभाषित नहीं किया गया है जिसका तात्पर्य उस उत्पादक से हो जो निर्यात करता है । अतः इस बात पर ध्यान दिए बिना कोई उत्पादक निर्यातक है और इस बात पर भी ध्यान दिए बिना कि कोई उत्पादक निर्यात करता है, उत्पादक और निर्यातक दोनों पृथक मार्जिन के निर्धारण के पात्र हैं । यदि कोई निर्यातक उत्पादक नहीं है तो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित जांच (18:20) करना कठिन होगा बशर्ते संबंधित उत्पादक ने उत्पादन लागत के बारे में सूचना प्रदान न की हो । कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित वह अर्थ निरूपण न्यायोचित है जिसमें निर्यातक या उत्पादक की पात्रता की मांग की गई है । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने निर्यातक या उत्पादक शब्द को निर्यातक के रूप में पढ़ लिया है जबकि ऐसा मामला नहीं है ।
- कि सुमितोमो कारपोरेशन एशिया पी टी ई लि. ने पोलिप्रोपीलीन के टर पोलिमर्स का निर्यात किया है जिसमें तीन मोनोमर अर्थात् प्रोपीलीन, एथीलीन और बुटीन निहित हैं । अतः वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं । अत्यंत सावधानी के रूप में सुमितोमो का डी जी ए डी से सविनय निवेदन है कि अंतिम जांच परिणाम में इस

आशय कास्पष्ट उल्लेख किया जाए कि टर पोलीमर जांच के दायरे में नहीं आते हैं । मैग्नेट यूजर्स एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2003 (157)) ई एल टी 150 (ट्रि-डेल) में माननीय सेस्टेट ने संबद्ध वस्तु के ऐसे ग्रेडों और प्रकारों को ऐसी वस्तु में शामिल करने की परंपरा के खिलाफ स्पष्ट निर्णय दिया है जिनका घरेलू उद्योग विनिर्माण नहीं करता है, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है ।

घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नलिखित प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध दायर किए हैं :

- कि घरेलू उद्योग अपने आवेदन में पूर्व में किए गए सभी अनुरोधों, टिप्पणियों और अन्य अनुरोधों को दोहराता है और उन पर भरोसा करता है । उक्त अनुरोधों को संक्षिप्तता की वजह से यहां दोहराया नहीं गया है । जिस किसी तथ्य या अभिकथन को विशेष रूप से इंकार किया गया माना जाएगा ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने निम्नानुसार जांच की है :

- प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वीकार किया है और यह पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस जांच के दौरान उन्होंने अधिकांश मुद्दे उठाए हैं । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में इन मुद्दों पर उचित और पर्याप्त विचार किया गया है । इसके अलावा, कुछ मुद्दों पर विशेष रूप से पुनः विचार किया जा रहा है । इसके अलावा जिन मुद्दों को पहली बार उठाया गया है उन पर भी निम्नानुसार विचार किया जा रहा है :-
- जहां तक घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के बारे में दिए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन का क्षति विश्लेषण पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इसमें निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान पॉलीप्रोपीलीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में इस अवधि की तुलना में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया था और वर्ष 2008-09 में कीमत में विश्व भर में गिरावट आई है और आर आई एल की प्रचलित कीमतें प्रचलित बाजार कीमतों की रेंज में थीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस समय प्रचलित बाजार कीमतों में भी भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन प्रदर्शित हो रहा था बहरहाल वैश्विक मंदी से संबद्ध वस्तु के पाटन पर लाइसेंस नहीं मिलता है ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने परिकल्पित क्षति का दावा किया है, प्राधिकारी ने 23 अगस्त, 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया है और प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-11 के साथ पठित नियम 11 की अपेक्षानुसार विवेकपूर्ण ढंग से किया है ।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षति रहित कीमत का गलत निर्धारण किया गया है, निराधार है क्योंकि प्राधिकारी ने पहले से अपनायी जा रही सुसंगत पद्धति के अनुसार क्षति रहित कीमत की गणना की है ।
- जहां तक एकसोन गोबिल द्वारा यह दावा करते हुए कि सिंगापुर पर शुल्क जारी नहीं रखा जा सकता, सऊदी अरब से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के बारे में दिए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । अतः किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि 30 दिसंबर, 2011 की सी.शु. अधिसूचना सं. 130/2011-सी.शु. के तहत केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सऊदी अरब से हुए आयातों पर शुल्क समाप्त कर दिया था परंतु प्राधिकारी के 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में कोई दोष नहीं पाया था। वस्तुतः शुल्क समाप्त करने वाली अधिसूचना भविष्यलक्षी प्रभाव के स्वरूप की है इसलिए
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना और आंकड़ों की जांच करने पर मै. मरुबेनी को शून्य शुल्क प्रदान किया गया था और इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक कोई सूचना रिकॉर्ड में नहीं है । जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रारंभिक जांच परिणाम की तुलना में पाटन मार्जिन में उध्वगामी संशोधन किया गया है, ऐसा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद तथा उसकी प्रमुख निविष्टि की कीमत में उतार-चढ़ाव को स्वीकार करते हुए प्राधिकारी द्वारा किए गए माह-वार विश्लेषण के परिणामस्वरूप किया गया है ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षति मार्जिन का प्रकटन किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि क्षति मार्जिन अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत पर आधारित होता है और चूंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई और गोपनीय मानी गई सूचना/आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए क्षति मार्जिन का प्रकटन नहीं किया जा सकता ।
- जहां तक मै. ओमान पॉलीप्रोपीलीन एल एल सी के इस तर्क का संबंध है, कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता की पुष्टि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने या जांच शुरू करने से पूर्व डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से नहीं की गई थी और यह कि जांच इन्फोडाइव आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी और प्रारंभिक जांच परिणाम भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए थे जिन्हें स्वयं प्राधिकारी ने जांच करने के बाद त्रुटिपूर्ण पाया गया था और यहां तक कि इन्फोडाइव के आंकड़ों में माप की गलत इकाई भी बताई गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई पाटनरोधी जांच एक ऐसी कमिक प्रक्रिया होती है जिसमें

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे सूचना/आंकड़ों के स्वरूप और विषय वस्तु में सुधार होता जाता है। स्वाभाविक है कि प्राधिकारी के पास किसी समय विशेष पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सही सूचना/आंकड़ों पर विचार किया जाएगा और ऐसा ही वर्तमान मामले में भी किया गया है। प्राधिकारी ओ पी पी के लिए सामान्य मूल्य के अपने निर्धारण को दोहराते हैं क्योंकि इसका सही निर्धारण किया गया है। जहां तक क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी 23 अगस्त, 2010 के अपने जांच परिणाम पर भरोसा करते हैं और इन्हें संक्षिप्तता की वजह से यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

- जांच अवधि के चयन के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि वर्तमान मामले में जांच की अवधि का उचित चयन किया गया था जिसमें इस विषय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े शामिल थे। तथापि, जांच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और संबद्ध वस्तु की कीमतों में अत्यधिक घट-बढ़ पर विचार करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण व्यवहार्य सीमा तक माह वार आधार पर किया गया था।

एक्सोन मोबिल के अन्य बातों के साथ-साथ इस तर्क के बारे में कोई दम नहीं है कि शुल्क भेदभावपूर्ण है।

- जहां तक इनाबाटा सिंगापुर पी टी ई लि. के इस तर्क का संबंध है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों में से एक उत्पाद एक यौगिक है और इसलिए यह जांच के दायरे से बाहर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा, यह कहना सही नहीं होगा कि यौगिक विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है और वह जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में अपने अंतिम जांच परिणाम को दोहराते हैं। जहां तक मै. इनाबाटा सिंगापुर पी टी ई लि. के संबंध में पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि मै. इनाबाटा ने काफी देर से सूचना प्रदान की थी। तथापि, विलंबित उत्तर के बावजूद निर्यातक द्वारा दायर सूचना/आंकड़ों की जांच की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया गया था कि टी पी सी द्वारा परिशिष्ट 2 में दिए गए निर्यात के ब्यौरे के अनुसार केवल तीन सौदों का निर्यात ही इनाबाटा के जरिए किया गया है जबकि परिशिष्ट-2 में इनाबाटा ने 5 सौदे दर्शाए हैं। इनाबाटा द्वारा ये सौदे कथित रूप से सितंबर, 2008 और नवंबर, 2008 दर्शाए गए थे, इस प्रकार टी पी सी तथा इनाबाटा द्वारा यथा सूचित भारत को किए गए निर्यातों का मिलान नहीं किया गया था। उनके द्वारा सूचित भारत को किए गए निर्यातों के बीच मिलान के अभाव में प्राधिकारी नोट करते हैं और यह दोहराते हैं कि वह इनाबाटा के लिए पृथक निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं कर

सके । जहां तक इनाबाटा के इस अनुरोध का संबंध है कि उनसे कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या की मांग नहीं की गई थी, यह सही नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी परंतु विसंगति के बारे में उन्होंने कोई उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया था । इसके बावजूद भी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा नए सिरे से किए गए अनुरोधों के संबंध में उनसे आगे चर्चा की गई थी । चर्चा के दौरान यह पाया गया है कि टी पी सी द्वारा दर्शाए गए दो सौदों का फोतलदान मै. इनाबाटा ने एक अन्य व्यापार कंपनी अर्थात् मै. इन्द्राको ट्रेडिंग पी टी ई लि., सिंगापुर से खरीद कर किया था और बाद में मै. टी पी सी ने उक्त माल की पुनः पूर्ति कर दी थी । यह देखा गया है कि मै. इन्द्राको ने इस जांच में कभी सहयोग नहीं किया गया है और इस प्रकार मै. इनाबाटा के पक्ष में पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करना संभव नहीं है । पहले खरीदने और बाद में पुनः पूर्ति करने से निर्यात सौदों की श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है क्योंकि प्राधिकारी के पास इस नई कंपनी मै. इन्द्राको ट्रेडिंग पी टी ई लि. द्वारा संबद्ध वस्तु की खरीद और उसके द्वारा किए गए एस जी व्यय तथा इन सौदों पर प्राप्त लाभ के बारे में कोई सूचना नहीं है । यह नोट करना खेदजनक है कि मै. इनाबाटा ने काफी देर से 27 जुलाई, 2012 को किए गए अपने अनुरोधों में मै. इन्द्राको ट्रेडिंग पी टी ई लि. से की गई वस्तु की खरीद का खुलासा नहीं किया गया है जो प्राधिकारी की मदद करने का कोई उचित तरीका नहीं है ।

- जहां तक इनाबाटा सिंगापुर, पी टी ई लि. के इस तर्क का संबंध है कि सिंगापुर और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार ("सीका") का अनुपालन नहीं किया गया है, यह निराधार है क्योंकि जांच के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे ।
- जहां तक सुमितोमो कार्पो. एशिया पी टी ई लि. के इस तर्क का संबंध है कि क्षति का संचयी निर्धारण अपेक्षित नहीं था और अंतिम जांच परिणाम में क्षति मापदंडों की जांच उचित नहीं है । प्राधिकारी ने 23 अगस्त, 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम में दिए गए क्षति विश्लेषण पर भरोसा किया है और उसे दोहराते हैं ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया था और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय

आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं। जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया था या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया था, अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली थी, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए थे। इसे ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का पुनरावलोकन अपेक्षित नहीं है।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कुछ ऐसे निर्यातकों/उत्पादकों को तरजीह दी गई है जो असहयोगी रहे हैं और परिणामतः उन्हें लाभ प्रदान किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कुछ प्रतिवादियों ने अतिरिक्त सूचना/आंकड़े दायर किए थे जिनके आंकड़े प्रारंभिक जांच परिणाम के चरण पर त्रुटिपूर्ण पाए गए थे। उक्त सूचना/आंकड़ों की जांच और उसके यथोचित सत्यापन के बाद उन पर अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ विधिवत विचार किया गया था। मै0 सेबिक ने मै. यानसाब यानबू नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी और मै. सऊदी कयान के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया था कि इन उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया है।
- जहां तक "टर-पॉलीमर" को जांच के क्षेत्र और दायरे में शामिल किए जाने के बारे में दिए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निराधार है क्योंकि जांच की शुरुआत में भी "पॉलीप्रोपीलीन" (अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन के होमोपॉलीमर तथा पॉलीप्रोपीलीन के को पॉलीमर और एथीलीन) के क्षेत्र और दायरे को सीमित कर दिया गया था और इस प्रकार टरपॉलीमर जांच के क्षेत्र और दायरे में नहीं था। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अनुसार "टर पॉलीमर" विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं था और इस प्रकार इसे जांच के दायरे से उचित ढंग से अलग रखा गया है। आगे यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत करते समय विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "पॉलीप्रोपीलीन" (अर्थात् पॉलीप्रोपीलीन के होमोपॉलीमर तथा पॉलीप्रोपीलीन के को पॉलीमर और एथीलीन) को स्पष्टतः परिभाषित किया गया था।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सऊदी अरब, जो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, के अपवर्जन से घरेलू उद्योग को सतत क्षति के अनिवार्य दौर से गुजरना होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सऊदी अरब पर शुल्क को केन्द्र सरकार की 30 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 130/2011-सी.शु. के तहत समाप्त कर दिया गया है।
- प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि उसने सार्वजनिक फाइल में समस्त संगत सूचना की प्रतियां उपलब्ध कराई थीं जो जांच के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध थीं।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी कीमत कटौती पर मौन है, प्राधिकारी 23 अगस्त, 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम में उसके द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के आकलन का कीमत कटौती एकमात्र मानदंड नहीं है और प्राधिकारी द्वारा किसी मामले विशेष में अन्य बातों के साथ-साथ अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री या अत्यधिक कीमत हास जैसे अन्य मापदंडों पर विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां घरेलू उद्योग पहुंच कीमत की बराबरी करने का विकल्प चुन सकता है जिससे उसे मात्रात्मक क्षति नहीं हो सकती है परंतु इससे कीमत मापदंड के बारे में क्षति हो सकती है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क का नियतन संदर्भ कीमत पर होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क की सिफारिश मामले के गुणदोष पर विचार करते हुए की गई थी और इस चरण पर इस मुद्दे का पुनरावलोकन अपेक्षित नहीं है। ?
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मै. इतोचू को पृथक व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत को हुए निर्यातों की पूर्ण श्रृंखला से संबंधित सूचना की पुष्टि नहीं की जा सकती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। यह देखा गया था कि मै. इतोचू ने जांच अवधि के दौरान टी पी सी से संबद्ध वस्तु की खरीद कर उसका निर्यात किया था और उसके द्वारा दायर की गई सूचना/आंकड़ों के आधार पर पृथक व्यवहार प्रदान किया गया था। इस सूचना का सत्यापन भी उचित समझी गई सीमा तक किया गया था।

जहां तक घरेलू उत्पादकों की ओर से दिए गए इस तर्क का संबंध है कि "शुल्क संयोजन" नियम 17 (3) के प्रतिकूल है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में प्राधिकारी की पद्धति अब स्पष्ट तौर पर सुस्थापित है और इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रकटन विवरण के पश्चात्तात किए गए अनुरोध

9. प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं। जिन मुद्दों को दोहराया गया है, उन्हें संक्षिप्तता की वजह से दोहराया नहीं गया है।

- मै. एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. ने प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए इस आशय के दस्तावेजों के अनुसार 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में शुल्क तालिका का शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है जिसमें एडवांस्ड पोलिप्रोपीलीन कं. के स्थान पर एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल्स कं. दर्शाया जाए।

- मै. इनाबाटा सिंगापुर पी टी ई लि. ने प्रकटन विवरण के प्रति निराशा जाहिर की है । यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले में इनाबाटा को कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और अंतिम जांच परिणाम तथा उसके अनुसरण में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना से असंतुष्ट इनाबाटा ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से इंकार के आधार पर माननीय न्यायाधिकरण में एक अपील दायर की । माननीय न्यायाधिकरण ने इसी अधिसूचना (पोलीप्रोपीलीन) के संबंध में दूसरी सुनवाई के मुद्दे पर उसके पूर्ववर्ती रिमांड आदेश के सुनवाई के मुद्दे पर उसके पूर्ववर्ती आदेश के मद्देनजर सभी अपीलों का निपटान कर दिया ।

यह अनुरोध किया गया है कि इनाबाटा ने रिमांड कार्यवाही में विवादास्पद 2 सौदों से संबंधित दस्तावेजों सहित समस्त सूचना दे दी है । निर्यातित वस्तु (सभी 5 सौदों के लिए) का उत्पादन टी पी सी ने किया है । आखिरी दो सौदों के संबंध में तात्कालिकता को देखते हुए निर्यात वस्तु की आपूर्ति टी पी सी की वस्तु के मौजूदा स्टॉक से की गई थी जिसकी कुछ दिन बाद टी पी सी द्वारा पुनः पूर्ति कर दी गई थी । प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह माना है कि चूंकि रिमांड के चरण पर पुनः पूर्ति के तथ्य का पहली बार उल्लेख किया गया है इसलिए इनाबाटा की कार्यवाई भ्रामक है । 31 जुलाई, 2012 को मामला अधिकारी के साथ हुई चर्चा के दौरान इनाबाटा के काउंसेल को यह सूचित किया गया था कि उसके उत्तर की क्रम सं. 4 और 5 पर उल्लिखित सौदे पुनः पूर्ति के हैं और इसलिए उन पर शुल्क संयोजन के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टी पी सी से सीधी की गई आपूर्तियां नहीं हैं । इन चर्चाओं के आधार पर इनाबाटा के काउंसेल ने इस आशय का एक पत्र दिया था कि :

- (i) इनाबाटा के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार भारत को निर्यातित सभी पांचों (5) परेषण टी पी सी द्वारा उत्पादित वस्तु के थे; और
- (ii) चूंकि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण दो सौदे टी पी सी द्वारा पुनः पूर्ति के थे इसलिए माननीय प्राधिकारी द्वारा इनाबाटा के मार्जिन का निर्धारण शेष तीन (3) निर्यात सौदों के आधार पर किया जा सकता है ;

आगे यह अनुरोध किया गया है कि इनाबाटा को इस मुद्दे की जानकारी कभी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसके पास टी पी सी के गोपनीय आंकड़ों तक पहुंच नहीं थी । माननीय प्राधिकारी की यह कार्यवाई भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीका) के अनुच्छेद 2.7.2 का स्पष्ट उल्लंघन है । माननीय प्राधिकारी ने तथाकथित विसंगति का उल्लेख केवल पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम में किया था । माननीय प्राधिकारी को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि अंतिम जांच परिणाम के बाद हितवत्त पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाता है । अतः यदि ऐसा नहीं

होता तो यह स्वाभाविक है कि वर्तमान जैसे मामले में माननीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के 14 मई, 2012 के विविध आदेश सं. एडी/एम/2-4/2012-सी यू (डी बी) के आदेशों के अनुसरण में ही और माननीय प्राधिकारी के हस्तक्षेप से इनाबाटा अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की स्थिति में था । इनाबाटा ने आगे अनुरोध किया है कि यदि माननीय प्राधिकारी ने सभी निर्यातकों (चुनिंदा को छोड़कर) को शामिल करने के लिए मौके पर सत्यापन के दायरे को बढ़ाया होता तो यह विसंगति उसी समय (केवल 5 निर्यात सौदे) उजागर हो गई होती और इनाबाटा उचित समयावधि के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम रहा होता ।

ओमान प्रोलीप्रोपीलीन एल एल सी

- इसने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराने की मांग की है और यह बताया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5.3 (ख) में प्राधिकारी के लिए जांच की शुरुआत के चरण पर ही प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच करनी अपेक्षित है । सत्यापन और प्रकटन विवरण जारी किए जाने के चरण तक प्राधिकारी के पास डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । केवल अंतिम जांच परिणाम के समय ही प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों की जांच की थी ।
- ओमान के सामान्य मूल्य का पुनः परिकलन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.2.1 के अनुसार किया जाना चाहिए । ओ पी पी ने कई बार यह अनुरोध किया है कि उसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 1 जुलाई, 2007 से शुरू किया था । वर्ष 2008 उसके उत्पादन का पहला पूर्ण वर्ष था । ओ पी पी अपनी फीड स्टॉक ओमान रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल ("ओ आर पी सी") से प्राप्त करता है जिसने भी अपना प्रचालन लगभग उसी समय शुरू किया था । शुरुआती उद्यम होने के कारण ऐसी कई विकट समस्याएं आई जिससे उचित क्षमता के मुकाबले उत्पादन कम हुआ । उत्पादन के प्रथम पूर्ण वर्ष अर्थात् 2008 के लिए उत्पादन 1,61,850 मी.ट. का हुआ है जो 340,000 मी.ट. की नेमप्लेट क्षमता का केवल 48% है । जांच अवधि के लिए उत्पादन 266,220 मी.ट. की क्षमता के मुकाबले 112464 मी.ट. का हुआ है अर्थात् 42.2% का क्षमता उपयोग हुआ है ।
- उत्पादन में आरंभिक अंतरनिहित समस्याओं का सामना करने के अलावा ओ.आर.पी.सी. से फीड स्टॉक की आपूर्ति के अभाव के कारण एक अन्य असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी परिणति भी उसी रूप में हुई है । वस्तुतः ओ पी पी ने डिलीवरी की कमी के कारण ओ आर पी सी से क्षतिपूर्ति का दावा भी किया है । यह कंपनी फीड स्टॉक की आपूर्ति हेतु ओ आर पी सी से स्वतंत्र है जिसे पाइपलाइनों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और कंपनी

के लिए दूसरे आपूर्तिकर्ता का सहारा लेना संभव नहीं है क्योंकि संयंत्र का लेआउट केवल रिफाइनरी से कच्ची सामग्री प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार किया गया है और जिसमें भारी लागत आएगी तथा ऐसे परिवर्तन हेतु संयंत्र के लेआउट में परिवर्तन करना होगा। तदनुसार ओ पी पी ने अनुरोध किया था कि इस असामान्य स्थिति के कारण निर्धारित लागत की प्राप्ति पर मानक क्षमता के आधार पर विचार किया जाए न कि वास्तविक उत्पादन अर्थात् जांच अवधि के लिए 266, 220 मी.ट. की क्षमता के आधार पर। इस संबंध में ओ पी पी ने आई सी डब्ल्यू ए आई द्वारा जारी प्रशासनिक व्यय संबंधी संगत लागत लेखा मानक का प्राधिकारी को हवाला दिया है जो ऊपरी व्यय की प्राप्ति के बारे में सामान्यतः स्वीकृत लागत लेखा सिद्धान्त है। यदि प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुरोधों पर विचार किया जाता तो घाटे पर हुई बिक्रियां 20 प्रतिशत से कम रही होतीं और तदनुसार लाभ पर हुई बिक्रियों पर विचार करना अपेक्षित था जिससे कम सामान्य मूल्य निकाला जा सकता था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शुरुआती अवधि में किसी कंपनी की उत्पादन लागत काफी अधिक रहती है। यद्यपि यह अपने उत्पादन की बिक्री वैश्विक कीमतों पर करती है परंतु इसकी उत्पादन लागत इस चरण पर अधिक होने की संभावना है। ऐसे मामलों के लिए हम प्राधिकारी का ध्यान पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.2.1 की ओर आकर्षित करना चाहेंगे जिसमें उल्लेख है कि :

“..... लागत का समुचित समायोजन लागत की उन अनावर्ती मदों जिनसे भावी और/अथवा वर्तमान उत्पादन में लाभ मिल सकता है, के लिए या ऐसी परिस्थितियों के लिए किया जाएगा जिनमें जांच अवधि के दौरान लागत शुरुआती प्रचालनों के कारण प्रभावित होती है।”

उपर्युक्त अनुरोधों को आगे बढ़ाते हुए यह दोहराया जाता है कि ओमान के खिलाफ वर्तमान जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई पाटन और क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास क्षति के बारे में एक अत्यंत कमजोर मामला है और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायोचित नहीं है। किसी भी हालत में संबद्ध वस्तु के संबंध में सऊदी अरब पर एक बार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को वित्त मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना के तहत रद्द (भेदभावपूर्ण तरीके से) कर दिया गया है, इसलिए घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति मौजूद नहीं है। उपर्युक्त टिप्पणियां अपनी शिकायतों के निवारण हेतु न्यायाधिकरण और न्यायालय (उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय) में जाने के ओ पी पी के अधिकार के प्रति किसी पूर्वाग्रह से अधिक है।

मै. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि. ("एच पी एल")

- एच पी एल ने रिलायंस इंड लि. द्वारा दायर अनुरोधों का समर्थन किया है। इसके अलावा, उसके द्वारा पहले उठाए गए मुद्दों को दोहराया नहीं गया है। इसने निम्नानुसार उल्लेख भी किया है :
 - प्रारंभिक जांच परिणाम में पाटन मार्जिन अंतिम जांच परिणाम में निकाले गए मार्जिन से काफी अधिक था।
 - सऊदी अरब, जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, के अपवर्जन से घरेलू उद्योग को सतत क्षति के अनिवार्य दौर से गुजरना पड़ेगा। इसकी भरपाई भी अपेक्षित है। राज्य का यह दायित्व है कि वह खासकर उन तबकों, जहां ऐसी किसी नीति का किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। प्राधिकारी को उसके विचाराधीन उत्पाद में शामिल सऊदी अरब की व्यापार कंपनियों के कृत्यों के कारण क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए और इस शुल्क को घरेलू उद्योग की भरपाई करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए अन्य कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए और साथ ही साथ प्राधिकारी द्वारा यह सिफारिश की जानी चाहिए कि सऊदी अरब को अलग नहीं रखा जाएगा क्योंकि इससे अन्यथा राज्य की समूची प्रक्रिया इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक निष्फल प्रक्रिया बन जाएगी।
- ऐसे किसी देश का गलत अपवर्जन जो पाटन कर रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है : सऊदी अरब को गलत ढंग से अलग रखा गया है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य के सभी निर्णयों में निष्पक्षता और पारदर्शिता का घटक होना चाहिए और ऐसे अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग मापदंड लागू नहीं किए जा सकते। जहां जाहिर तौर पर पाटन किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा रही है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण सऊदी अरब का मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए कुल मिलाकर ऐसा मामला है जिसमें सऊदी अरब द्वारा प्रस्तुत मूल्य के विपरीत वास्तविक मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इसमें वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के वर्षों के लिए इन्फोर्डाइव से प्राप्त संबद्ध उत्पाद की खपत, उत्पादन, निर्यात और आयात आंकड़ों का हवाला दिया है और यह तर्क दिया है कि इसके लिए भारत में पोलिप्रोपीलीन के आयात पर नियंत्रण लगाए जाने की जरूरत है।

- प्राधिकारी से उस पाटनरोधी शुल्क की पुनः गणना करने का अनुरोध है जिसके अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित मात्रा से अधिक होने की संभावना है ताकि घरेलू उद्योग को उचित संरक्षण प्राप्त हो सके ।
- एक्सोन मोबिल कैमिकल एशिया पैसिफिक; सुमितोमो कार्पोरेशन एशिया पी टी ई लि. ने कोई अतिरिक्त मुद्दा नहीं उठाया है परंतु उन्होंने क्षति संबंधी अनुरोधों का गहन विश्लेषण करने की मांग की है । मै. सऊदी बेसिक इंड. कार्पो., सऊदी अरब (सेबिक); मै. मरुबेनी ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है ।

मै. हाइड्रो एस एंड एस के अनुरोध

- प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के प्रकटन से इंकार किया है । क्षति रहित कीमत को गोपनीय माना जा सकता है । तथापि, क्षति मार्जिन को गोपनीय आंकड़ा नहीं माना जा सकता ।
- जांच अवधि के चयन के मुद्दे पर प्राधिकारी ने मार्च, 2008 से दिसंबर, 2008 के रूप में जांच अवधि के निर्धारण/चयन से संबंधित मुद्दे पर उचित विचार नहीं किया है । इस अवधि से किस प्रकार पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी, मात्रा और सीमा का सत्य एवं स्पष्ट पता चल सकेगा जबकि वस्तुस्थिति यह है कि उक्त अवधि खास बाजारी स्थिति द्वारा प्रभावित थी ।
- प्राधिकारी ने क्षति जांच के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर विचार नहीं किया है । प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्कों की जांच नहीं की है । प्राधिकारी ने अपने उस अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया है जिसे माननीय सेस्टेट ने 14 मई, 2012 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया है ।
- निर्यात निष्पादन का प्रकटन न किए जाने के मद्देनजर क्षमता उपयोग में गिरावट के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अनुरोध है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के निर्यात निष्पादन में भारी गिरावट आई है ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी कीमत कटौती पर मौन हैं, प्राधिकारी 23 अगस्त, 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण पर भरोसा करते हैं । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती क्षति के आकलन का एकमात्र मापदंड नहीं है और अत्यधिक कीमत ह्रास या अत्यधिक कीमत न्यूनीकरण जैसे अन्य मापदंड हैं जिन पर अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकारी द्वारा किसी मामले में विचार किया जा सकता

है । ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें घरेलू उद्योग पहुंच कीमत की बराबरी का विकल्प चुन सकता है जिससे उसे मात्रात्मक क्षति नहीं हो सकती है परंतु इसके फलस्वरूप उसे कीमत मापदंडों के बारे में क्षति हो सकती है । इस संबंध में अनुरोध है कि अब यह स्वीकृत स्थिति है कि आयातित वस्तु के कारण कीमत कटौती हुई है और केवल मामूली कम कीमत पर बिकी पाई गई है । कम कीमत पर बिकी की पुनः गणना क्षति रहित कीमत के निर्धारण के बाद इस प्रकार निकाले गए आंकड़ों से की गई है जिसका निर्धारण कृत्रिम रूप से बढ़ोत्तरी करके और अधिक से अधिक 22 प्रतिशत के रूप में आर ओ सी को तय कर के किया गया है ।

- शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर होना चाहिए क्योंकि नियत शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण मिलेगा । क्योंकि शुल्क का प्रभाव इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना प्रयोक्ता उद्योग पर पड़ेगा कि संबद्ध वस्तु का आयात अपाटित कीमत पर किया जा रहा है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नियम रूप में शुल्क के स्थान पर परवर्ती शुल्क लागू करें और उसे रूपयों में संग्रहीत करें ।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

- ए टी एम ए का निर्णय उन मामलों पर लागू होता है जिनमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुनवाई का विशिष्ट अनुरोध किया जाता है :- इस संदर्भ में यह दोहराया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ए टी एम ए निर्णय उक्त मामले के तथ्यों के परिपेक्ष्य में था जिसमें माननीय न्यायालय ने यह रिकॉर्ड किया था कि ए टी एम ए द्वारा सुनवाई का विशिष्ट अनुरोध किया गया था । तथापि, यह निर्विवाद तथ्य है कि मै. एडवांस पैट्रोकेमिकल्स ने किसी सुनवाई के लिए नहीं कहा और इस प्रकार यह तथ्य पूर्णतः अलग है । सादर निवेदन है कि माननीय न्यायालय ने ए टी एम ए के मामले में स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया है कि यदि सुनवाई की मांग की जाती है और नए निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी अनुमति नहीं देते हैं तो अंतिम जांच परिणाम और अंतिम अधिसूचना रद्द की जा सकती है । तदनुसार ऐसे मामले में जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के अनुसरण में किसी पक्षकार द्वारा किसी सुनवाई की मांग नहीं की गई है, वहां ए टी एम ए निर्णय पर विचार नहीं किया जाता है ।
- निर्णयोपरांत सुनवाई का मुद्दा केवल उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है - मै. एडवांस पैट्रोकेमिकल्स या किसी अन्य पक्षकार को यह छूट नहीं है कि वह माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष निर्णयोपरांत सुनवाई का मुद्दा उठाएं । यदि वे सेस्टेट के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उक्त पक्षकारों को सेस्टेट के निर्देश के खिलाफ कानून में उपलब्ध उचित निवारण का अनुपालन करना होगा ।

- मै. सेबिक को पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और उत्तर दायर करने में विलंब की माफी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के उपबंधों के खिलाफ दी गई है ।
- टरपोलीमर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर होना चाहिए — टर पॉलीमर कोपालीमर का एक भाग है जहां तीसरा मोनोमर एक प्रतिशत से कम होता है जबकि एथीलीन प्रमुख कोमोनोमर रहती है और इस प्रकार यह विचाराधीन उत्पाद की भाग होनी चाहिए । इस बात को दोहराया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने टर पॉलीमर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का दावा किया है । इस संदर्भ में अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद के अपवर्जन की मांग करने को सिद्ध करने का दायित्व ऐसे अपवर्जन का दावा करने वाले पक्षकार पर था । सिद्ध करने के ऐसे दायित्व की पूर्ति किए बिना ऐसा अपवर्जन कानूनन दोषपूर्ण था ।
- शुल्क संयोजन नियम 17 (3) के प्रतिकूल है ।
- मै. इतोचू को पृथक पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और मै. मरुबेनी के बारे में निष्कर्षों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।
- यह भी निवेदन है कि वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के जरिए सिफारिशें करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी स्पष्ट तौर पर यह दर्ज करें कि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम रिमांड निर्देशों के अनुसार दर्ज किए गए हैं और इसलिए इन्हें मूल अंतिम जांच परिणाम की तारीख से जारी किया गया माना जाए । ऐसी रिकॉर्डिंग विगत में केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बचाव हेतु आवश्यक है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है । हालांकि प्राधिकारी संक्षिप्तता की वजह से पूर्ववर्ती पैराग्राफों में मुद्दों की गई जांच को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तथापि, यह उन मुद्दों का समाधान कर रहे हैं जिन्हें इस विषय पर स्पष्टता की वजह से उठाया गया है ।

- जहां तक मै. एडवांस्ट पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, पूर्व में एडवांस्ट पॉलीप्रोपीलीन कं. लि. के नाम से ज्ञात की ओर से दायर अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 92 में इस जांच के प्रयोजनार्थ रिकॉर्ड में कंपनी के नाम में परिवर्तन को नोट किया था परंतु असावधानीवश इसका उल्लेख शुल्क तालिका में नहीं किया गया था । अतः प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि 23 अगस्त, 2010, के अंतिम जांच

परिणाम के शुल्क तालिका के क.सं. 5 के कॉलम सं. 6 को एडवांस्ट पॉलीप्रोपीलिन कंपनी कं बजाए मै. एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी पढ़ा जाए ।

- मै. इनाबाटा, सिंगापुर पी टी ई लि. के अनुरोधों को नोट किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. इनाबाटा ने इस विषय पर जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में कोई अनुरोध दायर न करने का विकल्प चुना और प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद ही अपने अनुरोध दायर किए । विलंबित उत्तर होने के बावजूद इनकी जांच की गई थी और ऐसे दोनों निर्यात सौदों जिनका प्रदर्शन टी पी सी के आंकड़ों में नहीं किया गया था परंतु जिन्हें प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण से पूर्व इनाबाटा की निर्यात बिक्री के सौदों में दर्शाया गया था, के बारे में वास्तविक स्थिति को समझने के लिए कंपनी के काउंसिल के साथ चर्चा की गई थी । कंपनी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है । जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने यह माना था कि निर्यात वाणिज्यिक मात्रा में नहीं थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी का स्पष्ट तर्क यह था क्योंकि उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया था कि "इनाबाटा ने जांच अवधि के दौरान अत्यंत अल्प मात्रा में केवल 5 खेपों का निर्यात किया है जिन्हें न तो इनाबाटा द्वारा प्रतिनिधिक निर्यात कहा जा सकता है और न ही घरेलू उद्योग को किसी भी रूप में क्षति पहुंचाने वाले निर्यात" । इसके बावजूद कंपनी को जांच के दौरान आगे अनुरोध दायर करने के लिए अवसर प्रदान किए गए थे । यह स्वीकार किया गया है कि कंपनी के काउंसिल को आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करने हेतु अंतिम जांच परिणाम से पूर्व एक अवसर दिया गया था परंतु वह इस अवसर के बावजूद इसे स्पष्ट करने में समर्थ नहीं रहे । इसके बजाए कंपनी ने यह उल्लेख करते हुए 27 जुलाई, 2012 को ही अपने अनुरोध दायर करने की मांग की कि वह पूर्व में अपने अनुरोध दायर नहीं कर सकी है ।

कंपनी द्वारा 27 जुलाई, 2012 को दायर अनुरोधों की प्राधिकारी ने जांच की थी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि उत्पादक अर्थात् टी पी सी, सिंगापुर के साथ कई समस्याओं के कारण मै. इनाबाटा ने अपने भांडागार में उपलब्ध टी पी सी ग्रेड के सामान्य स्टॉक से पोतलदान की व्यवस्था की थी और उसने सी आई एफ आई सी डी दिल्ली को फॉरवर्डर के जरिए वस्तु को भेजा था । एक ई-मेल के तहत कंपनी को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया था कि किए गए पोतलदान की खरीद मै. टी पी सी से की गई थी और ये टी पी सी ग्रेड से संबंधित थे; इस आशय की पूर्ण श्रृंखला को स्पष्ट किया जाए कि मै. टी पी सी सिंगापुर से वस्तु की खरीद किस प्रकार की गई थी और उसका पोतलदान सामान्य स्टॉक से कैसे किया गया था । कंपनी को यह स्पष्ट करने की भी सलाह दी गई थी कि क्या वह किसी अन्य उत्पादक से भी वस्तु की खरीद कर उसकी बिक्री करती है । इसके उत्तर में कंपनी के प्रतिनिधि ने 31 जुलाई, 2012 को मामला अधिकारी से भेंट की । बातचीत के दौरान प्राधिकारी ने उस पूर्ण श्रृंखला को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार मै. टी पी सी सिंगापुर

से वस्तु खरीदी गई है और तत्पश्चात् सामान्य स्टॉक से उसे किस प्रकार भेजा गया है । यह पाया गया था कि वस्तु की वास्तविक खरीद इनाबाटा ने अन्य व्यापार कंपनी अर्थात् इंट्रा को ट्रेडिंग पी टी ई लि. से की थी जिसे टी पी सी ने बाद में पुनः पूर्ण कर दिया था जबकि 27 जुलाई, 2012 को दायर अपने अनुरोधों में मै. इनाबाटा ने यह बताया था कि ग्राहक के तात्कालिक अनुरोध को पूरा करने के लिए उसने अपने भांडागार में उपलब्ध सामान्य स्टॉक से पोतलदानों की व्यवस्था की थी और अपने भांडागार से सी आई एफ/आई सी डी, दिल्ली तक वस्तु को भेजने की व्यवस्था की थी । इस प्रकार 31 जुलाई, 2012 को हुई बातचीत के दौरान यह नोट किया गया था कि जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातित वस्तु की वास्तवि में खरीद मै. इंट्राको ट्रेडिंग पी टी ई लि. से की गई थी । यह नोट किया जाता है कि मै. इंट्राको ने इस जांच में कोई सहयोग नहीं किया है । इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि अंतिम जांच परिणाम हेतु इस जांच में विश्लेषण माहवार आधार पर किया गया था और प्राधिकारी ने मै. इंट्राको द्वारा टी पी सी से संबद्ध वस्तु की की गई खरीद और ऐसा करते समय उसके द्वारा किए गए एस जी ए व्यय के बारे में रिकॉर्ड में कोई आंकड़ा नहीं पाया है । मै. इनाबाटा का यह तर्क कि प्राधिकारी को इन सौदों की अनदेखी करनी चाहिए और उसके पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए, इन सभी तथ्यों की ओर आंख मूंद लेने के समान होगा । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. इनाबाटा के लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

- जहां तक मै. ओमान पॉलीप्रोपीलीन एल एल सी के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने अपने दावों को इन्फोइडाइव इंडिया प्रा.लि. से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित किया था क्योंकि उस चरण पर डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इसे प्रथमदृष्टया साक्ष्य माना गया था । जांच के दौरान डी जी सी आई एंड एस के सौदेवार आंकड़े प्राप्त हो गए जिनकी प्राधिकारी ने जांच की थी । निर्यातों की न्यूनतम मात्रा के दावे का निर्धारण करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के सौदेवार आंकड़ों पर कंपनी के काउंसेल के साथ विधिवत चर्चा की गई थी और इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि उन्हें टिप्पणी करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया था ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.2.1 के अनुसार ओमान के सामान्य मूल्य का पुनः परिकलन किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.2.1 का संगत उद्धरण निम्नानुसार है :-

“जब तक इस उप पैराग्राफ के अंतर्गत लागत आबंटनों में पहले से प्रदर्शित न किया जाए, लागतों का समुचित समायोजन लागत की उन अनावर्ती मदों के लिए किया जाएगा जिनसे

भावी और/अथवा वर्तमान उत्पादन को लाभ मिलेगा या फिर ऐसी परिस्थितियों के लिए किया जाएगा जिनमें जांच अवधि के दौरान लागत शुरूआती प्रचालनों द्वारा प्रभावित होती है ।”

प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में उसके द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-8 में कंपनी द्वारा किए गए दावों को स्वीकार किया था और इस प्रकार यह तर्क देना गलत होगा कि शुरूआती लागत की अनुमति नहीं दी गई थी । मौके पर सत्यापन रिपोर्ट की भागीदारी कंपनी के साथ विधिवत की गई थी जिसमें भी कंपनी द्वारा किए गए शुरूआती दावे का कोई उल्लेख नहीं था । इसके उत्तर में कंपनी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया । किसी भी हालत में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.2.1 में प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह इसे उस स्थिति में लागू कर सकता है जब इसका प्रदर्शन लागत आबंटन में नहीं किया गया हो । यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने अपना दावा जांच की अंतिम घड़ी में किया है । अतः प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उसने सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया था और इसके लिए निर्धारित सामान्य मूल्य में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है । जहां तक ओ आर पी सी द्वारा फीड स्टॉक की आपूर्ति न किए जाने का संबंध है, निर्धारित सामान्य मूल्य में इस निमित्त भी कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है ।

- मै. हल्डिया पेट्रोकेमिक्स लि० (एच पी एल) के अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि उसने रिलायंस इंड. लि. द्वारा दायर अनुरोधों का समर्थन किया है । जहां तक इसके इस तर्क का संबंध है कि प्रारंभिक जांच परिणाम में पाटन मार्जिन अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित मार्जिन से काफी अधिक था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्यों की गलत समझदारी पर आधारित है । पाटनरोधी जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जांच की कार्यवाही जैसे-जैसे आगे बढ़ती है वैसे-वैसे सूचना/आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है । इसके अलावा यह नोट किए जाने की जरूरत है कि मामले के तथ्यों और गुणदोष पर विचार करते हुए अंतिम निर्धारण में माहवार विश्लेषण करने का निर्णय लिया गया था ।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षति मार्जिन का प्रकटन किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके प्रकटन से क्षतिरहित कीमत का भी प्रकटन हो जाएगा जिसे हितबकद्ध पक्षकार ने छुपाया है और यह कहा है कि यह गोपनीय है ।
- प्राधिकारी ने क्षति से संबंधित मुद्दे की जांच की है और यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण इस विषय पर पाटनरोधी नियमों के अनुसार समुचित रूप से किया गया है और इस वजह से 23 अगस्त, 2010 की अंतिम जांच परिणाम में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है । आगे यह नोट किया जाता है कि माननीय सेस्टेट ने 14 मई, 2012 के अपने आदेश के तहत प्राधिकारी के जांच परिणाम को बिल्कुल भी रद्द नहीं किया है अपितु, ए टी एम ए के निर्णय के मददेनजर मामले को वापस भेजा है ।

- जहां तक शुल्क के स्वरूप का संबंध है, प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि मामले के तथ्यों और गुणदोष के आधार पर इसमें परिवर्तन करने की कोई वजह नहीं है।
- जहां तक ए टी एम ए के निर्णय को लागू करने के बारे में दिए गए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्रवाई माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में की गई है और हितबद्ध पक्षकारों को कोई मुद्दा उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाना चाहिए।
- प्राधिकारी ने इस तर्क में कोई गुण नहीं पाया है कि मै. मरुबेनी के बारे में निर्धारण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान जांच परिणाम रिमांड निर्देशों के अनुसार दर्ज किए गए हैं।

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस विषय पर किए गए अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच करने और मामले के विधिक उपबंधों तथा तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार दिनांक 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में कोई उपांतरण न्यायोचित नहीं है।

निष्कर्ष

12. माननीय सेस्टेट के आदेशों के अनुसार मौखिक और लिखित अनुरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के बाद प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराग्राफों में उनकी जांच की है। सभी पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी पूर्व में निकाले गए और 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम में दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

13. अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश की पुष्टि करते हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में जारी की गई दिनांक 19 नवंबर, 2010 की अधिसूचना सं. 119/2010-सी.शु. तथा दिनांक 30 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 130/2011- सी.शु. के अधीन है। प्राधिकारी आगे यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 23 अगस्त, 2010 के अंतिम जांच परिणाम की शुल्क तालिका की कम सं. 5 के कालम सं. 6 को "एडवांस्ड पोलीप्रोपीलिन कं." के बजाए " मै. एडवांस्ड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी" पढ़ा जाए।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th August, 2012

Subject : Post-Decisional Oral Hearing on Anti-Dumping Investigations concerning imports of post-decisional hearing on anti-dumping investigation concerning imports of 'Polypropylene' originating in or exported from Oman, Saudi Arabia and Singapore.

No. 14/5/2009-DGAD.—In pursuance of the Hon'ble Tribunal (CESTAT's) Misc. Order No. AD/M/2-4/2012-CU(DB) dated 14th May, 2012, a Post-decisional hearing was held on 6th July, 2012 on the captioned subject, wherein the interested parties that had participated in the instant investigation were requested to participate.

2. Upon conclusion of the said hearing, the interested parties that had made their oral submissions were advised to file the written submissions within the stipulated time as per the AD Rules. They were also advised to file the rejoinders thereafter.

3. The written submissions and rejoinders filed by the interested parties, to the extent considered relevant, have been duly considered in this statement. Submissions made by interested parties have been examined by the Authority as follows:

Written Submissions made on behalf of M/s Saudi Polyolefins Company, Saudi Arabia, M/s Advanced Petrochemical Company, Saudi Arabia, M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia, M/s Marubeni Chemical Asia Pacific Pte. Ltd, M/s Oman Polypropylene LLC, Oman, M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore, M/s Inahata Singapore Pte Ltd., Singapore, M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore

4. The following submissions, in brief, have been made on behalf of these interested parties:

Submissions on behalf of M/s Saudi Polyolefins Company, Saudi Arabia; Advanced Petrochemical Company, Saudi Arabia and Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia

- These respondents have in essence reiterated their earlier submissions and have not raised new issue in the post decisional hearing.

Submissions on behalf of M/s Marubeni Chemical Asia Pacific Pte. Ltd

- The Authority, after conducting detailed investigation and verification at the premise of Marubeni, concluded that exports made by Marubeni were not causing injury to the domestic industry and therefore awarded zero duty to the exporter. That the same must be upheld.

- The export price of Marubeni during the POI was US\$ *** /MT whereas the export price claimed by the petitioner in its petition with respect to the imports from Singapore is US\$ 1473/MT. The significant difference between the export price of Marubeni and import price from Singapore itself establishes that the exports made by Marubeni could not have caused injury to the domestic industry.
- The price undercutting claimed by the petitioner is considering the average import price from Singapore which does not hold good. Marubeni fully cooperated in the present investigations and the data has been verified by the Authority. It was found that the export price of Marubeni was far higher than the average export price claimed by the petitioner in their petition.
- That the dumping margin in respect of its exports has been substantially revised upwards as compared to preliminary findings. It does not agree with the modification done in determining the dumping margin.
- The Authority should disclose their injury margin, as provided under the law since their injury margin is negative and therefore no duty should be payable in respect of their exports. The Authority had not disclosed the injury margin and it must be disclosed.
- They are not in agreement with the Authority with respect to the final findings with regard to scope of product under consideration, existence of like article, existence of dumping, existence of injury and causal link between dumping and injury.
- Marubeni has given interest bearing credits to its customers and such interests cost should be included in the landed price of imports in order to determine injury margin. The CIF price reported by the company was exclusive of such interest bearing credit.

Submissions on behalf of M/s Oman Polypropylene LLC, Oman

- The Accuracy of the evidence furnished by the Applicant was not corroborated with DGCI&S data before the initiation or before the issuance of preliminary findings. The Petition was initiated based on Info drive data and the preliminary findings were also issued on the basis of same data which the Authority has itself on examination found to be erroneous, in as much as, the wrong unit of measurement was stated in the info drive data. The Authority has wrongly calculated the Normal value for OPP. In the comments to the disclosure statement filed on behalf of OPP. The cost of production needs to be revisited by the Authority and necessary adjustments have to be made in accordance with the WTO Agreement.
- There is no causal link between the injury claimed by the Applicant Industry and the alleged imports as there is no volume effect of alleged dumped imports from Oman. There is no injury suffered by the applicant and the same can be demonstrated on the following parameters:-

- The sales of the Applicant Industry are far greater than the volume of subject imports that it is unlikely that the volume of imports could have any real impact on the volume of domestic sales.
- The capacity utilization shows an increasing trend. It is pointed out that in the POI Applicant's capacity utilization has shown a declining trend primarily due to their plant shut down at Jamnagar.
- The Domestic sales volumes has shown a rising trend, which is in pace with the rising Domestic Demand of the subject goods. It is seen that the Domestic sale of the Applicant Industry has increased by 66% points during the POI when compared with the base year. Thus, there is no volume effect of the dumped imports on the Applicant Industry.
- There was a trend of falling polypropylene prices faced by the producers all over Asia as also other parts of the world and losses on this account incurred cannot be attributed to dumped imports. That the decline in profitability, ROCE, and cash flow as a result cannot be linked with imports from the subject countries and is on account of general decline in Polypropylene prices, worldwide in particular during April-December 2008 (POI).
- The productivity, employment and wages have shown no negative impact due to imports of subject goods and the Authority has noted that the productivity is not a cause of injury to the Applicant Industry. That there has been a decrease of the average inventory level from 100 (in the base year 2005-06) to 73 in the POI showing an improved off take. In fact the inventory level is far lower in POI than at any time during the entire injury investigation period.

Submissions made on behalf of ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore

- The selection of period of investigation is not in accordance with the recommendations of the Committee on Anti-Dumping Practices. The POI is a representative period, on the basis of which, a determination is to be made, as to whether there is existence of dumping and injury. The POI in the present case is too short and includes the months during which the movement of raw materials and polypropylene prices was erratic due to global recession. Any examination of facts during this POI would not yield accurate results, as during this POI the global prices of polypropylene, Naptha and crude fluctuated in a totally unpredictable manner. ExxonMobil submits that the POI should be fixed for a period of 18 months for a fair and proper analysis.
- The export performance of the domestic industry has affected their financial and economic situation, as they are facing anti-dumping proceedings in Brazil for export of the same product i.e., polypropylene. This initiation has been published as Circular No. 41 dated July 23, 2009 by the Ministry of Development, Industry and International Trade. Injury, if any, is caused by extraneous factors.

- The perusal of international prevailing prices of polypropylene during the period 2007-2008 and 2008-09 demonstrates that there is a great fluctuation in prices over a period of time and in the year 2008-2009 prices plummeted globally. The prices, as per RIL's price list, crashed below US\$ 1000 PMT. The said price when compared with prevailing Platts prices shows that RIL prevailing prices were in the range of prevailing market prices. On the contrary, exporters were charging higher prices because of their long term contract with buyers in the Indian market. Therefore, to say that the surge in exports resulted in injury to domestic industry on this account is fallacious and misrepresentation of global position in polypropylene business.
- During the period of investigation and in subsequent two quarters the global demand plunged and prices of polypropylene crashed even below 50% of its price. In absence of comparison of export sales, it can be submitted that possibly reduction in export or shut down of plant for any other reason may be the reason for under utilization of capacity. Polypropylene, being a petroleum base product, is linked with petroleum production, petroleum pricing and plastic industry across the world. The domestic industry cannot be isolated from the global market, especially when the domestic industry is catering to around 3% of global consumption of polypropylene.
- The reduction claim on account of return on capital and cash flow on index basis cannot be believe to be true so far it is claimed on the basis of dumped imports. The analysis of imports from subject countries vis-à-vis the total market share of the domestic industry during the relevant period in time would show that the argument that due to increase in imports from the subject country return on capital employed has gone down to 30 against the base level of 100 and in case of cash flow it has gone down to 48 against the base of 100., would hold no water.
- The claim of confidentiality coupled with the fact that the domestic industry is a monopolistic player in the domestic market, the anti dumping complaint is a gross abuse of the process of law.
- The doubtful data submitted by the domestic industry and claim of injury made on the basis of such data in absence of fair disclosure cannot be treated as reliable for imposing anti dumping duty against import from the subject countries.
- The loss claimed on account of liquidation of stock after September and October 2008 does not hold any substance. The Platts prices and domestic industry's own prices as available at the given website clearly shows that prices reduced drastically.
- There has been no injury whatsoever to the domestic industry from the import of the Subject Goods. In fact, the entire injury has been engineered by fixation of an inflated non- injurious price ('NIP') for the domestic industry. The cost of production has been adopted on a higher side. Additionally, a 22% return on investment has been included for arriving at the NIP. By fixing an inflated NIP, on a comparison of such NIP with the

landed value of imports, injury has been determined by the Respondent No. 1. The findings relating to injury are without any factual basis.

- That in the Disclosure Statement, the fair selling price for the domestic industry has been fixed by determining the profit as 22% return on investment or capital employed. It is submitted that the Anti-Dumping law cannot place the domestic industry in a position better than, if there was no dumping. It is submitted that either no profit or a reasonable profit, ought to have been fixed, based on the global profits in the industry during the Period of Investigation or the historical profits earned by the domestic industry, for a fair analysis.
- The entire RIL business has never achieved such a high ROCE (Reliance on Capital Employed) (22%) in the past decade. A 22% ROCE in 2008 for the PP business in India would be even more unrealistic in 2008 given the unusual economic conditions in that year, which (in RIL's words) experienced a "commodity prices trend reversal" with "a combination of sky rocketing oil prices and poor demand". Even the three largest global PP manufacturers do not typically achieve 22% ROCE, as may be noted from their consolidated results for 2007 and 2008. A more typical ROCE for the PP Industry in 2008, based on a survey carried out by an independent consultant, would be 1.41%.
- The inflated NIP requires revision, and the profit should be fixed based on industry norms or on historical levels of return on capital employed.
- The injury claimed by Domestic industry in the Polypropylene business is due to the unprecedented volatility in the crude oil prices, and not due to any injurious dumping of Polypropylene by EXXONMOBIL in India. The effect of such global trends cannot be attributed to the subject imports.
- Additional grounds for termination of this investigation: ExxonMobil submits that it had filed an appeal no. 2 of 2011 before the Hon'ble Customs Excise Service Tax Appellate Tribunal against the Final Findings No. 14/5/2009 –DGAD dated August 23, 2010 issued by the Designated Authority in the instant matter. In view of the partial withdrawal of the duties by the aforesaid Findings, ExxonMobil had also filed an application raising additional grounds before the Hon'ble Tribunal for termination of the aforesaid Findings. The Hon'ble Tribunal while disposing off the appeal of Exxon Mobil (based on its order of remand for de novo consideration by the Designation Authority passed in the connected matter) directed to raise the additional grounds before the Designated Authority. In view of the directions given by the Hon'ble Tribunal, ExxonMobil is reproducing herein below the additional grounds raised before the Hon'ble Tribunal for consideration:
 - The applicants made a representation to the Central Government vide its letter 12.01.2012 pointing out that in view of the withdrawal of the duties on the imports from Saudi Arabia, duties on Singapore could not be continued, as this

was discriminatory and contrary to the provisions of Rule 19 of the Anti-Dumping Rules. The applicants submit that in view of the partial withdrawal of the duties by the aforesaid notification, they crave leave to adduce the following grounds, in addition to the grounds already set out in the appeal.

- The appellants submit that the imposition of duties is based on the recommendations of the Authority, as regards existence of dumping, injury and causal link. For the purpose of injury analysis, the Authority has conducted a cumulative assessment of the injury caused by the imports from Saudi Arabia, Singapore and Oman. If the imports from Saudi Arabia are to be excluded, the findings on the aspect of injury rendered by the Authority would not sustain. Moreover, in a case, where the Authority has held that there is dumping from various sources, it is not open to the Central Government to impose duties on a selective/discriminatory basis. Reference in this regard has also been made to their submissions made before the Central Government stating, *inter alia*, that

On December 30, 2011 the Central Government has withdrawn the duties imposed on the imports from Saudi Arabia by Notification 130/2011 -Cus. EMCAP believes, that this may be for the reason, that the Central Government has formed a view that the findings rendered by the Designated Authority, are not factually and legally sustainable with regard to Saudi Arabia. In this context, EMCAP submits that the duty against the imports from Singapore is based on the very same findings of the Designated Authority and, therefore, if the findings are not appropriate for Saudi Arabia, they are equally inappropriate for levying duties on imports from Singapore. The duties by the same token, are required to be withdrawn against Singapore also. EMCAP submits that for the imposition of duties, the Central Government must be satisfied that the imports from the subject countries are at dumped prices and that consequential injury is caused from such imports on the local manufacturer. The entire findings of the Designated Authority on the aspect relating to injury, are based on a cumulative assessment of the effects of the imports from Saudi Arabia, Singapore and Oman.

The scheme of the Act and Rules, do not permit partial acceptance of the recommendations, for the reason, that paragraph (iii) of Annexure II to the Rules, provides that where imports of a product from more than country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Designated Authority shall cumulatively assess the effect of such imports. If the imports from Saudi Arabia are to be excluded from the analysis, the entire injury examination of the DA would no longer be valid. The recommendations of the DA, therefore, have to be accepted or rejected in whole and not in part. As the Central Government has partially rejected the finding, it must reject the entire findings.

- EMCAP submits that no separate analysis has been carried out by the Designated Authority, so as to ascertain whether there are injurious effects of the imports from Singapore on the domestic producer. The finding based on a cumulative assessment of injury would not hold, if the imports from Saudi Arabia are excluded. Existence of injury from the exports from Singapore has hence not been established in terms of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975. In the absence of any findings regarding the effects/consequences of the imports on the domestic producer from the imports from Singapore, the anti-dumping duties cannot be imposed. Section 9B provides that no duty shall be imposed under Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 unless a determination has been made that import of such article causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.
- No duty can be imposed on the imports from Singapore, as there is no determination on the aspect of injury. It is also not open to the Central Government to follow a policy of pick and choose with regard to the countries against which, it chooses to impose anti-dumping duties. Rule 19 of the Anti-Dumping Rules, provides that the duty shall be imposed on a non – discriminatory basis, that is, it shall be applicable to all imports of such articles, from whatever sources found dumped. As the Central Government has already withdrawn the duties on Saudi Arabia, it can not continue the duties on imports from Singapore and Oman, since the imposition of duties on these countries would be discriminatory and contrary to the provisions of Rule 19 of the Rules.
- *EMCAP further submits that it has not dumped its products into India and submits that the findings of the Designated Authority are, based on an erroneous interpretation of the facts. The entire findings relate to data collected for a period, when on account of recessionary forces, there was a very wide fluctuation in prices of raw materials and finished goods. It is on account of selection of such a period, artificial margins have been derived. The injury analysis is also flawed, as the landed prices of the imports from Singapore was almost at par with the prices at which goods have been sold by domestic producer during the relevant period. Therefore, there is a total absence of any dumping or consequential injury arising from the exports made by EMCAP. In view of the fact that, the Central Government has withdrawn the duties on Saudi Arabia, EMCAP submits that there is no further justification for continuation of the duties in respect of Singapore. EMCAP, therefore, requests that the duties in respect of its exports to India, may be withdrawn forthwith. The appellants submit that in view of the withdrawal of duty on imports Saudi Arabia the duties against Singapore are totally unjustified and discriminatory.*

Submissions made on behalf of Inabata Singapore Pte Ltd., Singapore

- The selection of period of investigation is not in accordance with the recommendations of the Committee on Anti-Dumping Practices. The POI is a representative period, on the

basis of which, a determination is to be made, as to whether there is existence of dumping and injury. The POI in the present case is too short and includes the months during which the movement of raw materials and polypropylene prices was erratic due to global recession. Any examination of facts during this POI would not yield accurate results, as during this POI the global prices of polypropylene, Naptha and crude fluctuated in a totally unpredictable manner. The changes in the raw-material prices were significant and consequently, it was difficult to estimate the costs of production for fixation of prices.

- One of the products exported by them is a compound and, therefore, outside the scope of the investigations. ISPL submit that compounds and polypropylene are not substitutable, technically or commercially. The compound is a prepared product which is tailor made for a particular application and may include materials other than polypropylene. Whereas the polypropylene can be converted to a compound. The reverse is not true. Therefore, while polypropylene has multiple applications, the compound can be used only for the application for which it has been prepared.
- In the final findings, the Authority has held that since the exports by ISPL were not in commercial quantities, no margin of dumping can be determined for it. ISPL submits that in terms of sub Rule (3) of Rule 17 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and For Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules), the Authority is required to determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation. In this regard, it is submitted that the said Rules do not make any distinction for the purposes of Rule 17.
- The sale between the producer and the appellant is a domestic one. The sale to customers in India, by ISPL is an export sale. TPC has correctly accounted for the transactions as domestic sales. In fact, for the purposes of the questionnaire response, TPC has also tried to identify separately those domestic sales which are in the course of export. Therefore, merely because the transactions have been reflected as domestic sales by TPC does not reflect any discrepancy in the two responses.
- There is Non-compliance of Comprehensive Economic Cooperation Agreement ("CECA") between Singapore and India. Article 2.7.2 of the CECA read together with Paragraph 6 of Annex II of Article VI of GATT 1994 imposes an obligation on the Designated Authority to use its "best endeavours" to procure information in case it is of the view that complete information has not been provided by ISPL in its Exporter Questionnaire ("EQ") response. In view of the above submission, ISPL is of the view that where information previously submitted is not accepted or regarded as incomplete because of a new claim or allegation raised by the domestic industry, ISPL should be granted a reasonable opportunity to respond to that new claim or allegation.
- That the export performance of the domestic industry has affected their financial and economic situation, as they are facing anti-dumping proceedings in Brazil for export of

the same product i.e., polypropylene. This initiation has been published as Circular No. 41 dated July 23, 2009 by the Ministry of Development, Industry and International Trade. Injury, if any, is caused by extraneous factors.

- That it is not justified to assume that against the production of 15,17,688 MT during the period of investigation (annualized), domestic industry has suffered losses on account of price under cutting and return on investment due to import from subject countries (6.83% of the domestic industry's production).
- That the Designated Authority has not taken a view that the domestic industry has always abused its monopolistic position, being the largest polypropylene manufacturer and seller in India. That the global reduction of price of polypropylene (third and fourth quarter of 2008) during the investigation period might have affected the total sales, including the domestic sales and reduction on return of capital, cash flow etc cannot be said to due to imports from the subject countries.
- That the Designated Authority, in its findings has stated that there is increase in market share of domestic sales from 89% to 92%. However, it has been stated that "it appears that domestic industry has chosen to retain the market share at the cost of its realization". In this regard, it is being submitted that prices of exporter were contracted prices, which were determined on the basis of Platts average prices for the previous quarter/half year. This aspect can be confirmed by comparing the two transactions of exports made by Inabata in the month of September and November 2008 wherein inspite of prevailing price of around US \$ 1000 per MT, ISPL charged US \$ 2076 per MT, which were much higher than the prevailing market prices of RIL or Platts Prices. Therefore, to say that the higher prices were charged by the exporters whereas domestic industry could not increase the prices is incorrect, as the higher prices were charged due to long-term contracts
- That the domestic industry has cleverly chosen the period of investigation of nine months and has not gone beyond December 2008, as the global price of polypropylene plummeted in the last quarter of 2008. The price came down by more than 50%, which resulted in loss to the global industry due to demand shrinkage across the world. Any increase imports during the period of investigation, cannot result into loss of profit on the ISPLI of 100 to 20 on the base year of 2005-2006. That the domestic industry is trying to establish a new economic theory by alleging loss of profit to the tune of 80% due to reduction in imports from the subject country by 10% (approximately).
- That during the period of investigation and in subsequent two quarters the global demand plunged and prices of polypropylene crashed even below 50% of its grade. In absence of comparison of export sales, it can be submitted that possibly reduction in export or shut down of plant for any other reason may be the reason for under utilization of capacity. Polypropylene, being a petroleum base product, is linked with petroleum production, petroleum pricing and plastic industry across the world. The domestic industry cannot be

isolated from the global market, especially when the domestic industry is catering to around 3% of global consumption of polypropylene.

- That the analysis of imports from subject countries vis-à-vis the total market share of the domestic industry during the relevant period in time would show that the argument that due to increase in imports from the subject country return on capital employed has gone down to 30 against the base level of 100 and in case of cash flow it has gone down to 48 against the base of 100., would hold no substance.
- That the claim of confidentiality coupled with the fact that the domestic industry is a monopolistic player in the domestic market, the anti dumping complaint is a gross abuse of the process of law.
- That the data submitted by the domestic industry and claim of injury made on the basis of such data in absence of fair disclosure cannot be treated as reliable for imposing anti dumping duty against import from the subject countries.
- That the loss claimed on account of liquidation of stock after September and October 2008 does not hold any substance. The platts prices and domestic industry's own prices as available at the given website clearly shows that prices reduced drastically.
- That there is a high possibility that the injury claimed by Domestic industry in the Polypropylene business is due to the unprecedented volatility in the crude oil prices, and not due to any injurious dumping of Polypropylene by ISPL in India. The effect of such global trends cannot be attributed to the subject imports.

Submissions made on behalf of Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore

- That the selection of period of investigation not in accordance with the recommendations of the Committee on Anti-Dumping Practices. The POI is a representative period, on the basis of which, a determination is to be made, as to whether there is existence of dumping and injury. The POI in the present case is too short and includes the months during which the movement of raw materials and polypropylene prices was erratic due to global recession. Any examination of facts during this POI would not yield accurate results, as during this POI the global prices of polypropylene, Naptha and crude fluctuated in a totally unpredictable manner. The changes in the raw-material prices were significant and consequently, it was difficult to estimate the costs of production for fixation of prices.
- That the Cumulative Assessment of Injury is not warranted. The Designated Authority can cumulatively assess the effect of imports from more than one country, only when it determines that the cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles. The conditions of competition between Singapore and sales of domestic industry, are quite different from that of other countries (under to investigation). The exports from

Singapore were made at much higher prices, than the imports from other countries under investigation. The conditions of competition are therefore, quite different for Singapore, as compared to other countries. It follows that a separate assessment of injury should be carried out for Singapore. Also, the injury caused by the imports from Singapore, is negligible, the investigation would be liable to be terminated forthwith.

- That the examination of the injury parameters in the final findings is not appropriate for the following reasons. There is absence of volume effect of dumped imports and impact on domestic industry. That the decline in the capacity, production & capacity utilization due to plant shut down at Jamnagar. There is increase in sales of the domestic industry. The price underselling is negligible. That the decline in profitability due to other factors petrochemical companies globally are facing difficult times. The fact that domestic industry had profits belies the claim of injury. That the decline on return on capital employed by the domestic industry, if at all, has been caused due to factors, such as volatility in petroleum prices. The decline in cash flows, is widely prevalent in times of such severe recession. The domestic industry has increased the strength of its number of employees and increased the wages during the poi. There is no material to show that the ability to raise capital investment of domestic industry has been hampered in any way.
- That there is a high possibility that the injury claimed by Domestic industry in the Polypropylene business is due to the unprecedented volatility in the crude oil prices, and not due to any injurious dumping of Polypropylene by SCA in India. The effect of such global trends cannot be attributed to the subject imports.

Submissions made on behalf of Haldia Petrochemicals Ltd.

- That the excessive confidentiality claimed by exporters and erroneously accepted by the Designated Authority in clear violation of acceptable norm/law and trade notice/s.
- That comparing apples with oranges inasmuch as Designated Authority, in its Final Findings has calculated dumping margin by taking into account normal value of the producer and export value of the exporter. It is submitted that such an approach is not provided for under the provisions of the Indian Anti-Dumping law.
- That the indulgence has been given to certain exporters/producers who have been non-cooperative and consequently have benefitted since they were not declared non-cooperative. The Designated Authority in its Preliminary Findings had taken note of the fact that SABIC which sells the subject goods for two related entities namely, M/s. IBN Zahir and M/s. Yanpet has not provided any details in respect of Appendices 4 – 9. The Designated Authority had also observed that in the absence of the required information, the Authority is unable to carry out the ordinary course test.
- That the delay in filing of response by the exporters/producers should not have been condoned. Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules clearly provides that information is required to be furnished by the exporters, foreign producers and other interested parties

within thirty days of receipt of notice from the Designated Authority. Extension of time may be allowed by the Designated Authority only upon sufficient cause being shown.

- That the differentiation adopted by the Designated Authority in its final finding not correct inasmuch as having come to the conclusion that compounds are part of product under consideration has decided to treat ter-polymer as being not within the ambit and scope of investigation.
- That the Designated Authority has not holistically and extensively determined the injury to Domestic Industry.
- That the exclusion of Saudi Arabia which is a non-market economy would expose Domestic Industry for inevitable fate of continuous injury as this flank is admittedly not being covered by the Designated Authority.
- That the Designated Authority is a quasi judicial authority and hence bound by the principles of rule of law and natural justice. It should provide all the relevant information to the Domestic Industry and where it cannot, it must give detailed reasons to justify such non-disclosure.

Submissions made on behalf of Hydro S & S Ltd.

- That the period of investigation (i.e., 1st April 2008 to 31st December 2008) in the present case is too short and includes the months during which the movement of raw materials and polypropylene prices was erratic due to global recession. Moreover as evident from the subsequent anti-dumping investigation initiated by the authority in respect of imports from Korea, USA and Taiwan, the economic figures of the domestic industry itself would show a marked improvement in performance in short span of time immediately after the period of investigation in the instant matter.
- That there is violation of Rule 6 and 7. The DI has completely ignored the principal of due process, whereby DI could present its data in any manner to suit its interest while right of the other interested parties to defend their interested are seriously prejudiced.
- That the closure of plant has been projected as a result of dumping of subject goods from subject countries. Further the petitioner has not provided any meaningful disclosures with respect to the capital employed which would have been used for the purpose of capacity enhancement. It is submitted that the period of plant closure was for the purpose of capacity enhancement and not on account of dumping. Moreover the case of the petitioner as evident from the finding is based on price underselling rather than price undercutting which clearly shows that the imports were at the price higher than the domestic selling price of the petitioner. Hence the claim of injury on account plant closure is not sustainable and liable to be rejected.
- That the definition of the product under consideration by the petitioner has been intentionally left wide open to enlarge its scope to cover even all those grades which are

neither produced by the petitioner company nor it has capability of producing goods of such specifications.

- INJURY: That though the demand of subject goods have increased, Imports from subject countries declined considerably during the POI. The sale of the petitioner declined marginally during POI but the same is on account of plant closure by the petitioner but equally notable fact is that the imports from subject countries also declined during the said period.
- That the market share of the domestic producers has remained same over the period while it may be observed that the market share of the Indian producers rather increased from 90 to 92% if compared with the POI and the preceding year, which makes it evident that injury, if any, to the domestic industry is not on account of imports of the subject goods but is on account of increasing competition among the domestic producers.
- That the Domestic industry has enhanced its capacity during POI. The capacity utilization of the petitioner remained high despite planned shutdown of the plant for about 4 weeks. It is pertinent to note that for one month during the POI (total 9 months) the Domestic Industry resorted to planned shutdown. This shut down was to increase the capacity to meet the difference between total demand and total domestic production. Therefore any loss of business caused to the domestic industry as a result of the planned shut down is solely due to the acts of the domestic industry and the imports of the alleged dumped goods cannot be held responsible for the same.
- That the landed value of the imports has increased significantly on one hand, and the imports have declined on the other hand, hence injury, if any cannot be attributed to imports. That the Profitability is affected due to suspension of production of the domestic industry.
- That the domestic industry has increased wages, which resulted in the increased cost. It is further submitted that neither the petitioner nor the Authority has explained the reasons and factors on account which the cost of production of the petitioner has increased significantly.
- That finding of the authority is silent on undercutting and only discussed the price underselling, which clearly implied that there is no price undercutting. Since there has been no price under-cutting it clearly establishes the fact that the landed value of the imported goods was higher than the domestic selling price of the petitioner.
- That though the numbers of employees are showing declining trend yet the wages of the employees is showing increasing trend. Which clearly show that the wages of the employees have been increased substantially which as in turn pushed the cost of production significantly.
- That the fixation of AD duty be on reference prices is warranted keeping in view the the Petitioner is not a producer of all types of Polypropylene. The production offered by the

petitioner is marred by both the issues of interrupted supplies and most importantly with respect to issue of quality and product consistency. Moreover de-valuation of Rupee would further increase the protection level for the petitioner as the imports have already become costlier.

Written Submissions made by the Domestic Industry

5. The following written submissions, in brief, has been filed on behalf the domestic industry:

- It has reiterated and relied on all the submissions made earlier in the application, comments and other submissions.
- The Authority should not grant individual dumping margin to M/s. SABIC as they have failed to provide vital and essential information to the DA. It is reiterated that SABIC ought to have been considered as a non-cooperative party.
- M/s Itochu cannot be granted an individual treatment or separate dumping margin as information relating to the complete chain of exports to India cannot be established. The Authority has consistently in other cases rejected the information of the exporters only on the ground that they have failed to complete the chain of exports to India.
- The delay in filing of the response has been condoned against the provisions of Rule 6(4) of the AD rules. The Authority can extend the period for filing the response only after sufficient cause is shown by the concerned interested party. From the perusal of the public file, it is clear that M/s SABIC had not even given the reasons for the delayed response. Therefore, there is no question of the DA extending the period. It needs to be appreciated that there is neither any legal provision for the DA to extend the period suo moto nor are there any such persuasive circumstances. Submission of grounds for seeking extension is a pre-condition for the DA to operate under Rule 6(4). Since it is an undisputed fact that no reasons had been given by the party, the Designated Authority could not have condoned such substantial delay in filing of the response.
- M/s SABIC had not provided the information for all the related companies who are engaged in the activity of the subject goods whereas legally they are required to give the information for all the related parties. It is an undisputed fact that M/s SABIC had not given the information for M/s Yansab Yanbu National Petrochemical Company and M/s Saudi Kayan who apparently are also engaged in the activity of the subject goods. In the absence of full information of a single economic enterprise and its related entities, they could not have been treated as cooperating exporters.
- The combination duties are contrary to Rule 17(3). In this context, it is submitted that the Designated Authority had calculated the dumping margin taking into account the Normal Value of the Producer and export price of Exporter. It is submitted, that there is no provision in law which permits the Designated Authority to determine combination duties. Moreover, this methodology can never lead to determination of individual dumping margin.

- The Authority in the final findings had excluded ter polymers from the scope of product under consideration without examination of submissions and settled law and practice on the subject. In the absence of details with regard to technical specifications, chemical composition, commercial and technical substitutability etc. from the interested parties, such exclusion was without any legal justification and basis. Further, no cogent basis to establish that the said polymer was not like article to product under consideration has been provided or placed on record.
- The onus of proof of seeking such exclusion was on the party claiming such exclusion. In the absence of discharge of such onus of proof, the exclusion was bad in law. Moreover, it is submitted that the Domestic Industry is capable of producing any grade and hence exclusion was granted without examination of the legitimate claims of the Domestic Industry. The Designated Authority failed to appreciate that ter polymer is part of copolymer where third monomer is less than 1% while ethylene remains the dominant co-monomer.

Rejoinder submissions made on behalf of M/s Advanced Petrochemical Company, Saudi Arabia, M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia, M/s Marubeni Chemical Asia Pacific Pte. Ltd, M/s ExxonMobil Chemical Asia Pacific, Singapore, M/s Inabata Singapore Pte Ltd., Singapore, M/s Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd., Singapore

6. The following rejoinder submissions, in brief, have been filed on behalf of these interested parties:
 - That the domestic industry has challenged the combination duty determined by the Designated Authority. Marubeni submits that the practice of the Designated Authority in this regard is now well established. No factual basis has been advanced by the domestic industry which requires reconsideration of the established practice. Given the nature of investigations and the fact that there is no change in legal or factual basis, nor any decision of any higher authorities, nor any factual basis established either by the domestic industry in the present case or otherwise, Marubeni submits that there is no necessity to review or reconsider the established practice in this regard. Furthermore, since Marubeni has not resorted to exports at low price and data provided by Marubeni clearly establishes that this export price is substantially higher than the prices at which goods have been sold by other suppliers in the Indian market, Marubeni submits that the company should not be penalized by anti dumping duty. Marubeni is not responsible for low price exports made by other trading companies and should not be penalized for the same.
 - That this practice of Authority of recommending combination duties in respect of cooperating exporters and trader exporters has not been successfully challenged at either the WTO or in India. Moreover, it's not required that all unrelated trader exporters cooperate in an investigation in order for a producer to be granted individual

determination. In a situation in which a cooperating trader exporter sourcing from many producers cooperates but not all the producers do then how can that be dealt with. In any case the fair way for any change in established practice would be to publish this through a trade notice and then apply it prospectively to investigations initiated after the concerned trade notice is published.

- That as far as the claim of the domestic industry that M/s SABIC should be treated as a non-cooperating exporter as it has not submitted information for all the related parties involved in the production, it is submitted that M/s SABIC filed responses for two producers, who had produced and sold the subject goods to M/s SABIC. The information was also verified by DGAD. Further, as regards the allegation that other related companies have not filed their responses, it may be mentioned that such producers had not engaged in commercial production of the subject goods. Hence, both the companies did not file a separate response. The claim of the domestic industry falls flat in view of the same.
- That it has been contended that the concept of combination duty is inconsistent with the law. ExxonMobil submitted that there is no basis for this submission as Rule 17 provides for a determination of an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation. Therefore, a separate margin can be determined either for the exporter or the producer. It is important to note that the term "exporter" has not been defined to mean an exporter which produces; the term "producer" has not been defined to mean a producer which exports either. Therefore, regardless of whether an exporter is a producer, regardless of whether a producer is an exporter, and regardless of whether a producer exports, exporters and producers are both eligible for determination of separate margin. In the case of an exporter which is not a producer it would be difficult to conduct the test relating to ordinary course of trade (18:20) unless information relating to cost of production has been provided by the concerned producer. There is nothing in the law to suggest the interpretation proposed by domestic industry which seeks to qualify the words exporter or producer is justified. In fact the domestic industry appears to read the word exporter or producer as exporter and producer, which is not the case.
- That Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd has exported TERPOLYMERS of polypropylene that contain three monomers i.e. propylene, ethylene and butene. Therefore, they are not covered within the scope of the product under consideration. As a matter of abundant caution, Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd. humbly requests DGAD to make an express mention in the final findings that TERPOLYMERS are not included within the scope of the investigation. The Hon'ble CESTAT in *Magnet Users Association vs. Designated Authority* [2003 (157) ELT 150 (Tri-Del)] has specifically ruled against the practice of including grades and types of the subject goods that are not manufactured by the domestic industry within the ambit of goods on which antidumping duties can be levied.

Rejoinder Submissions made by the Domestic Industry

7. The following rejoinder submissions, in brief, has been filed on behalf the domestic industry:

- That the domestic industry reiterates and relies on all the submissions made earlier in the application, comments and other submissions. The said submissions have not been repeated herein for the sake of brevity. Any facts or averments which are not specifically admitted hereinafter may be treated as specifically denied.

Examination by the Authority

8. The Authority has noted the submissions made by the interested parties and the same to the extent considered pertinent, have been examined as follows:

- The Authority has noted the submissions made by various interested parties in the instant matter and finds that most issues have already been raised by them during the course of this investigation by the Designated Authority. The Authority further notes that these issues have been appropriately and adequately addressed in the final findings dated 23rd August 2010. Nonetheless, some of the issues are being specifically addressed again. Besides, the issues that have been raised for the first time are also being addressed herein below.
- The Authority notes that on the examination of the information and data, M/s Marubeni was awarded zero duty and there is no new information on record necessitating any change in that position. As regards the contention that the dumping margin has been raised upwards as compared to preliminary findings; the same is a result of month-wise analysis undertaken by the Authority taking cognizance of volatility in the prices of the PUC and its major inputs during the POI.
- As regards the contention that injury margin should be disclosed; the Authority notes that as the injury margin is, *inter alia*, based on the NIP determined for the domestic industry and as the same is based on the information /data filed by the domestic industry on confidential basis and treated so; the injury margin cannot be disclosed.
- As regards the contention of M/s Oman Polypropylene LLC, that the Accuracy of the evidence furnished by the Applicant was not corroborated with DGCI&S data before the initiation or before the issuance of preliminary findings and that the investigation was initiated based on Info drive data and the preliminary findings were also issued on the basis of same data which the Authority has itself on examination found to be erroneous, in as much as, the wrong unit of measurement was stated in the info drive data; the Authority notes that an anti-dumping investigation is a gradual process wherein the nature and content of information/data improves as the investigation moves forward. It is but natural the best and correct information /data as is available with the Authority at a point of time would be considered by it and that's what has also been done in the instant matter as well. The Authority reiterates its determination of Normal value for OPP as the same has been appropriately determined. As regards the contentions pertaining to injury and causal link are concerned; the Authority relies upon its findings dated 23rd August 2010 and the same are not being repeated herein for the sake of brevity.

- As regards the submissions made by various interested parties in respect of the selection of period of investigation; the Authority reiterates that the period of investigation in the instant matter had been appropriately chosen, covering the most recent available data on the subject. However, considering significant movements in the prices of raw-materials and that of the subject goods during the POI, the analysis of the data was undertaken on a month-wise basis; to the extent the same was feasible.
- As regards the submissions that the export performance of the domestic industry; the Authority notes that the export performance of the domestic industry has not impacted injury analysis as the same does not include the figures for export.
- As regards the submissions that the international prices of polypropylene during the period 2007-2008 and 2008-09 witnessed great fluctuation in prices over a period of time and in the year 2008-2009 prices plummeted globally and that RIL prevailing prices were in the range of prevailing market prices; the Authority notes that the prevailing market prices at that point of time also were reflective of dumping of the subject goods in India. In any case, global recession should not give a license to dump the subject goods.
- As regards the contentions that notional Injury has been claimed by the domestic industry; the Authority relies upon its final findings dated 23rd August 2010 and the injury analysis has been done with due application of mind by the Authority as required under Rule 11 read with Annexure II of the Anti-Dumping Rules, 1995.
- As regards the contention that there has been an incorrect determination of the NIP is devoid of merits as the Authority has computed the Non-Injurious Price as per its consistent practice being followed over a period of time.
- As regards ExxonMobil's contentions referring to the revocation of the antidumping duties on the imports from Saudi Arabia claiming that duties on Singapore could not be continued; the Authority notes that it had recommended imposition of the Anti-dumping duties concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. Hence, there was no discrimination of any nature. Further the Authority notes that vide Customs Notification No. 130/2011-Customs dated 30th December 2011 the Central Govt. in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 has revoked the duties on imports from Saudi Arabia but without finding any fault with the final findings dated 23rd August 2010 of the Authority. In fact, the notification revoking the duties is prospective in nature and thus the contentions made by ExxonMobil, *inter alia*, that duties are discriminatory, are devoid of any merit.
- As regards Inabata Singapore Pte Ltd's contentions that one of the products exported by them is a compound and, therefore, outside the scope of the investigations; the Authority notes that the claim has not been substantiated. Besides, it would not be correct to state that compounds are not part of the product under consideration and reiterates its final findings as regards the scope of the product under investigation. As regards the issue of determination of separate dumping margin in respect of Inabata Singapore Pte Ltd's is

concerned; it has been noted that M/s Inabata had provided the information very late. However, despite the delayed response, the information/data filed by the exporter was examined. It was, *inter alia*, noted that as per the export details provided by TPC in Appendix 2, there are only 3 transactions which have been exported through Inabata whereas there are 5 transactions reflected in the Appendix 2 provided by Inabata. The two shipments reportedly made by Inabata in September 2008 and November 2008 were not reflected in TPC's data; thus the exports to India as reported by TPC and Inabata did not reconcile. In the absence of reconciliation between the exports to India reported by them, the Authority notes and reiterates that it cannot determine a separate export price and dumping margin for Inabata. As regards M/s Inabata submission that no explanation or clarification was sought from them; the same is not correct as the issue was discussed with the company's representatives but no cogent explanation was submitted by them regarding the discrepancy. Notwithstanding this, further discussions were held with the representatives of the company in terms of the fresh submissions filed by them. During the discussions, it is found that M/s. Inabata had shipped the two transactions that were not reflected by TPC, after procuring the goods from another trading entity known as M/s. Intraco Trading Pte Ltd. Singapore and subsequently M/s. TPC had replenished the said goods. It is seen that M/s. Intraco never cooperated in this investigation and hence it is not possible to determine an individual dumping margin in favour of M/s. Inabata. Buying first and replenishment later, does not complete the chain of export transactions as the Authority does not have any information regarding the procurement of the subject goods by this new entity M/s. Intraco Trading Pte Ltd and the SGA expenses that it may have incurred and profit made on these transactions. It is disconcerting to note that the fact of buying the goods from M/s. Intraco Trading Pte Ltd was not even disclosed by M/s Inabata in its submissions filed as late as 27th July 2012, which is not an appropriate way of assisting the Authority.

- As regards Inabata Singapore Pte Ltd's contentions that there is non-compliance of Comprehensive Economic Cooperation Agreement ("CECA") between Singapore and India; the same are devoid of any merit as ample opportunities were provided to all the stake holders during the course of the investigation.
- As regards Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd's contentions that the Cumulative Assessment of Injury not warranted and examination of the injury parameters in the final findings is not appropriate; the Authority relies upon and reiterates its injury analysis as reflected in its final findings dated 23rd August 2010.
- As regards contentions that excessive confidentiality has been claimed by exporters; the Authority notes that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority had accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. Wherever an interested party had refused access to, or had otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or had

significantly impeded the investigation, the Authority had recorded the findings on the basis of the 'facts available'. In view of the same, the issue does not require to be revisited.

- As regards the contention that the indulgence has been given to certain exporters/producers who have been non-cooperative and consequently have benefitted; the Authority notes that additional information/data was filed by some of the respondents whose data was found to be deficient at the preliminary findings stage. Upon examination of the said information/data and appropriate verification thereof as deemed fit, the same was duly considered for the purposes of the final findings. M/s SABIC had provided the clarification in respect of M/s Yansab Yanbu National Petrochemical Company and M/s Saudi Kayan that these producers had not engaged in commercial production of the subject goods.
- As regards the contention regarding inclusion of 'ter-polymer' within the ambit and scope of investigation is concerned; the Authority notes that the same is devoid of any merit as the very initiation of the investigation had restricted its ambit and scope as 'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene)' and thus 'ter-polymer' was not within the ambit and scope of the investigation. As per the application filed by the domestic industry, 'ter polymer' was not a part of the PUC, and hence it has been correctly excluded from the scope of the investigation. It is further noted that the product under consideration had been clearly defined while initiating the investigation viz. 'Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and co-polymers of propylene and ethylene)'.
- As regards the contention that the exclusion of Saudi Arabia, which is a non-market economy would expose the domestic industry for an inevitable fate of continuous injury; the Authority notes that the duties *vis a vis* Saudi Arabia have been revoked vide Central Government's Notification No.130/2011-Customs dated 30th December 2011 in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
- The Authority further notes that it had provided copies of all relevant information in the public file, which was available for inspection by all interested parties during the course of the investigation.
- As regards the contention that the Authority is silent on undercutting; the Authority relies upon the injury analysis undertaken by it in its final findings dated 23rd August 2010. Besides, the Authority notes that price undercutting is not the sole criterion for adjudging injury and that there are other parameters such as significant price depression or significant price suppression which may, *inter alia*, be considered by the Authority in a given case. There could also be a situation where the domestic industry may choose to match the landed prices, whereby it may not suffer a volume injury but as a result thereof suffer injury on price parameters.

- As regards the contention that the fixation of AD duty should be on reference prices; the Authority notes the duties were recommended considering the merits of the case and this issue is not required to be revisited at this stage.
- As regards the contention that M/s Itochu should not be granted an individual treatment as information relating to the complete chain of exports to India cannot be established; the Authority notes that the contention is baseless and devoid of merit. It was seen that M/s Itochu had exported the subject goods produced from TPC during the POI and based on the information/data filed by them, which was also verified to the extent deemed fit, an individual treatment was granted to them.
- As regards the contention on behalf of the domestic producers that 'Combination duties' are contrary to Rule 17(3); the Authority notes that the practice of the Authority in this regard is now fairly well established and therefore; there is no necessity to review the same.

Post-Disclosure submissions

9. The following submissions, in brief, have been made by the interested parties in response to the Disclosure statement. The issues that have been repeated are not being reproduced for the sake of brevity.

- M/s Advanced Petrochemicals Company has requested to issue a corrigendum to the duty table in the final findings dated 23rd August 2010 from Advanced Polypropylene Co to Advanced petrochemicals company in terms of documents filed before the Authority to this effect.
- M/s Inabata Singapore Pte Ltd has expressed its disappointment, with the disclosure statement. It has submitted that no fair opportunity has been given to Inabata in this matter and that aggrieved by the final findings and the Customs notification, issued pursuant thereto; Inabata filed an appeal before the Hon'ble Tribunal on grounds of denial of principles of natural justice. The Hon'ble Tribunal disposed off all the appeals, in view of its earlier remand order, on the second hearing issue, in respect of this very notification (Polypropylene).

It has been submitted that Inabata, has given all the information, including the documents relating to the disputed 2 transactions in the remand proceedings. The exported goods (for all 5 transactions) have been produced by TPC. In view of urgency, in respect of the last two transactions, the export goods were supplied from the existing stocks of TPC goods, which were replenished by TPC, a few days later. The Authority holds in the disclosure statement that since the fact of replenishment has been mentioned for the first time at the remand stage, the actions of Inabata are misleading. During the discussions held with the case officer on July 31, 2012; counsel for Inabata were informed, that the transactions at Sl. No. 4 and 5 of its response, were of replenishment, and therefore, could not be considered for purposes of combination duty, as they are not direct supplies from TPC. On the basis of these discussions, the counsel for Inabata, gave a letter to the effect that:

- (i) all the five (5) consignments exported to India, as reported in Inabata's response were of goods produced by TPC; and
- (ii) since the two transactions were case of replenishment by TPC, due to certain special circumstances, Inabata's margin could be determined by the Hon'ble Authority based on the remaining three (3) export transactions.

It has been further submitted that Inabata would have never found this issue as it had no access to the confidential data of TPC. This action of the Hon'ble Authority is a clear violation of the Article 2.7.2 of Comprehensive Economic Cooperation Agreement between India and Singapore (CECA). So called discrepancy was stated by the Hon'ble Authority only in the erstwhile final findings. The Hon'ble Authority is well aware of the fact that post-final finding, no opportunity of hearing is granted to the interested party. Therefore, it is but natural that Inabata was in a position to explain its position, such as in the instant case, only pursuant to the orders of the Hon'ble Tribunal (CESTAT's) Misc. Order No. AD/M/2-4/2012-CU (DB) dated 14th May, 2012 and also with the intervention of this Hon'ble Authority. Inabata has further submitted that had the Hon'ble Authority expanded its scope of on-site verification to cover all the exporters (as against the chosen ones), the said discrepancy could have been highlighted at that time (being only 5 export transactions) itself and Inabata would have been able to explain its position within the proper time frame.

Oman Polypropylene LLC

- It has sought to reiterate its earlier submissions and stated that Rule 5.3(b) of the Anti-dumping Rules requires the Authority to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided at the stage of initiation of the investigation itself. Till the stage of verification and issuance of disclosure statement, DGCI&S data was not available with the Authority. It was only at the time of Final Findings, when DGCI&S data was examined by the Authority.
- Oman's Normal Value should be reconstructed in accordance with the Article 2.2.2.1 of the Anti-Dumping Agreement. OPP has time and again submitted that it started its commercial production from 1st July 2007. The year 2008 was the first full year of production. OPP gets its feedstock from Oman Refinery and Petrochemical Company ('ORPC') which too started its operations almost at the same time. Being starts up ventures, there have been several teething problems which have led to lower production against the rated capacity. The production for the year 2008, the first full year of production, has been 161,850 MT which is only 48% of the nameplate capacity of 340,000 MT. For the POI the production has been 112464 MT against capacity of 266,220 MT i.e. capacity utilization of 42.2%.
- In addition to facing initial teething problems in production, there has been another abnormal situation arising on account of lack of feedstock supply from ORPC which has resulted in the same. In fact OPP has also filed claim for damages from ORPC on account of lack of delivery. The company is dependent upon ORPC for the supply of the

feedstock which is made available through pipelines and it is not possible for the company to switch over to another supplier because the plant layout is designed to get raw materials only from the refinery and it would entail substantial costs and change in plant layout for such switchover. Accordingly, OPP had submitted that due to this abnormal situation, recovery of fixed costs is considered on the basis of standard capacity and not the actual production i.e. on the basis of capacity of 266,220 MT for the POI. OPP had in this regard referred the Authority to relevant Cost Accounting Standard on Administrative Overheads issued by ICWAI and generally accepted cost accounting principles on recovery of overheads. If the above stated submissions were to be considered by the Authority; the loss making sales would have been less than 20% and according, all profitable sales was required to be considered thereby a lower normal value would have been derived. It is an admitted fact that the production cost of a company is very high during the start-up period. Though it sells its products at world prices, but its production costs are likely to be higher at that stage. For cases such as this, we would like to draw the Authority's attention towards the Article 2.2.2.1 of the Anti- Dumping Agreement clearly states that:

".... Cost shall be adjusted appropriately for those non-recurring items of cost which benefit future and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start-up operations."

In furtherance to the above submissions, it is reiterated that there is no dumping and injury to justify the present investigation against Oman. In addition, the Domestic Industry has a very weak case on injury and imposition of anti dumping duty is not justified based on the present facts and circumstances. In any event, once Anti dumping duty imposed on Saudi Arabia on the subject goods have been revoked (discriminatorily) by the Ministry of Finance vide notification dated 30 December 2011, no case of injury to the Domestic Industry, at all, exists. The comments above are without prejudice to OPP's right to approach the Tribunal and the Courts of law (including High Court and Supreme Court) for redressal of its grievances.

M/s. Haldia Petrochemicals Ltd. ('HPL')

- HPL has endorsed the submissions filed by Reliance Industries Ltd. Besides, the issues already raised by it have been reiterated. It has also stated the following : :
 - In the Preliminary Findings dumping margin was much more than that has been concluded in the final findings.
 - The exclusion of Saudi Arabia which is a non-market economy would expose Domestic Industry for inevitable fate of continuous injury. This also requires to be compensated. State is duty bound to ensure fairness and transparency in all its sections especially where any such policies can adversely affect someone. The Authority must determine the margin of injury due to acts of Saudi Arabia business entities involved in the product under consideration of Authority and increase the said duty on other entities to compensate and to protect the Domestic Industry simultaneously with the recommendations by Authority that Saudi Arabia should not

be excluded as otherwise entire exercise of State would come under the realm of being a colourable exercise.

- **Wrongful exclusion of a country which is dumping and harming Domestic Industry:** Saudi Arabia has been wrongly excluded and this is clear violation of Article 14 of the Constitution of India. In all decisions of the State the element of fairness and transparency should be there and different yardsticks cannot be applied for different countries where admittedly dumping is taking place and Domestic Industry is being injured. Saudi Arabia being a non-market economy is all the more reason for the Designated Authority to determine the real value as contradistinguished to value presented by Saudi Arabia.
- In relation to injury to Domestic Industry, it has referred to the production, consumption, export and import data for the subject product for the years 2008-2009 to 2011-2012 as derived from Infodrive and contended that the same necessitates imposition of control in import of polypropylene into India.
- The Authority is requested to rework the Anti-Dumping Duty which is likely to be in excess of what has been determined in the Final Findings and levy the same and thereby provide appropriate protection to the Domestic Industry.
- ExxonMobil Chemical Asia Pacific; Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd have not raised any additional point but have sought in-depth analysis of the injury submissions. M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC); M/s Marbueni have sought to reiterate their earlier submissions.

Submissions made by M/s Hydro S & S

- The Authority has denied the disclosure of injury margin. The Non injurious price may be treated as confidential. However the injury margin cannot be a confidential figure.
- On the issue of selection of period of investigation the Authority has not addressed the issue appropriately with respect to fixation/selection of period of investigation as March 2008 to December 2008. How the said period would lead to true and correct finding of existence, degree and extent of dumping and injury to the domestic industry, given the fact that the said period was marred by peculiar market situation.
- The Authority has not dealt any issue raised by the interested parties on injury examination. The Authority has not examined the contentions raised by the respondent. The authority has relied on its final findings which were set-aside by the Hon'ble CESTAT vide its order dated 14th May, 2012.

- The claim of the Petitioner with respect to decline in capacity utilization cannot be sustained in view of non-disclosure of export performance. It is submitted that it is an admitted position that the export performance of the petitioner has declined significantly during the period of investigation.
- As regards the contention that the Authority is silent on undercutting; the Authority relies upon the injury analysis undertaken by it in its final findings dated 23rd August 2010. Besides, the Authority notes that price undercutting is not the sole criterion for adjudging injury and that there are other parameters such as significant price depression or significant price suppression which may, inter alia, be considered by the Authority in a given case. There could also be a situation where the domestic industry may choose to match the landed prices, whereby it may not suffer a volume injury but as a result thereof suffer injury on price parameters. In this respect it is submitted that it is now admitted position that no price under-cutting has been caused by the imported goods and there is only finding marginal price under selling. The under selling is again derived from the figures so arrived after fixation of NIP which has been fixed by artificially increasing and fixing the ROCE as high as 22%.
- The duty should be on reference price basis as imposition of fixed duty will have a negative effect on the user industry and would provide undue protection to domestic industry as the implication of duty will fall upon the user industry irrespective of the fact that the subject goods are being imported at un-dumped prices. In view of the foregoing the Designated Authority is requested to revise the form of duty from fix to variable duty and be collected in rupee terms.

Submissions made by the Domestic industry

- ATMA decision is applicable in those cases where a specific request for hearing have been made by the interested parties.- In this context, it is reiterated that ATMA decision rendered by Hon'ble Supreme Court was in the context of the facts of that case wherein the Hon'ble Court had recorded that a specific request for hearing was indeed made by the ATMA. Moreover, it is an undisputed fact that M/s. Advance Petrochemicals did not ask for any hearing and hence the facts were clearly distinguishable. It is respectfully submitted that Hon'ble Court has held unequivocally in the case of ATMA that if hearing is sought and not given by new Designated Authority, the final finding and final notification are liable to be quashed. Accordingly, a case where a hearing is not sought by any party pursuant to the change of designated authority is not contemplated in the ATMA judgment.
- Issue of Post-decisional hearing can be raised only before appropriate Authority- It is not open for M/s Advance Petrochemicals or any other party to raise the issue of post-decisional hearing before the Hon'ble Designated Authority, If they were aggrieved by the decision of the CESTAT, said parties ought to have followed an appropriate remedy in law against the direction of the CESTAT.

- Individual dumping margin should not be granted to M/s SABIC and delay in filing of the response has been condoned against the provisions of Rule 6(4) of the anti-dumping rules.
- Ter polymer should be within the scope of Product under consideration - Ter polymer is a part of co-polymer where third monomer is less than 1% while ethylene remains the dominant co-monomer and hence should form part of the PUC. It is reiterated that interested parties have claimed exclusion of Ter polymer from the scope of product under consideration. In this context, it is submitted that the onus of proof of seeking exclusion of a product from the scope of product under consideration was on the party claiming such exclusion. In the absence of discharge of such onus of proof, the exclusion was bad in law.
- Combination duties are contrary to Rule 17(3).
- Individual dumping margin should not be granted to M/s Itochu and conclusions in respect of Ms Marubeni should be revisited.
- It is also prayed that the while making recommendations through the present Final Findings Designated Authority may specifically record that the present Final Findings are recorded in terms of remand directions and therefore may be deemed to have been issued from the date of original Final Findings. Such recording is necessitated to protect actions taken by Central Government in past.

Examination by the Authority

10. The issues raised by the interested parties in response to the Disclosure statement, to the extent considered pertinent, have been examined. While the Authority is not reproducing its examination of the issues in the preceding paras for the sake of brevity; it is addressing some of the issues that have been raised for the sake of clarity on the subject.
 - As regards request filed on behalf of M/s Advanced petrochemicals company formerly known as Advanced poly propylene company limited; the Authority notes that it had taken note of the change in name of the company on record for the purposes of this investigation in para 92 of the final findings dated 23rd August 2010 but inadvertently the same was not reflected in the duty table. Hence, the Authority recommends that column no 6 of Sr. no 5 of the duty table of the final findings dated 23rd August 2010 be read as M/s Advanced petrochemicals company instead of Advanced Polypropylene Co.
 - M/s. Inabata, Singapore Pte Ltd submissions have been noted. The Authority notes that M/s Inabata chose not to file any submission in response to the initiation notification on the subject and filed its submissions only after the issuance of the preliminary findings. Notwithstanding the delayed response, the same was examined and discussions were held with the company's counsel to understand the factual position as regards the two export transactions which were not reflected in the TPC data but were reflected in Inabata's

export sales transactions before the Authority's final determination. The company has, acknowledged this fact. As regards the contention that the Authority had considered that the exports were not in commercial quantity, the Authority notes that this was precisely the contention of the company as it had, *inter alia*, submitted that "Inabata has exported only five consignment of very small quantity during the period of investigation, which can neither be said to be representative exports by Inabata nor the exports causing injury to the domestic industry in any manner". Notwithstanding this, opportunities were available to the company to file further submissions during the course of the investigation. It has been acknowledged that an opportunity before the final findings was given to the company's counsel to explain the difference in the data but he was not able to explain the same, despite opportunity given to this effect. Instead, the company has sought to file its submissions only on 27th July, 2012; citing that it could not have filed a submission at an earlier date.

The submission dated 27th July 2012 filed by the company was examined by the Authority, wherein it was, *inter alia*, stated that because of several problems with the producer, namely, TPC, Singapore, M/s Inabata arranged the shipments from its common stock of TPC grade available in its warehouse and shipped the goods through its own forwarder to CIF ICD Delhi. Vide an e-mail, the company was provided an opportunity to explain along with the documentary evidence that the shipments made were procured from M/s TPC and pertained to TPC grade; explaining the complete chain as to how the goods were procured from M/s. TPC Singapore and shipped thereafter from common stock. The company was also advised to clarify whether it procures and sells the goods of any other producer also. In response thereto, the company's representative met the case officer on 31st July, 2012. During the interaction, the Authority sought to understand the complete chain as to how the goods were procured from M/s. TPC Singapore and shipped thereafter from common stock. It was found that the goods were actually procured by Inabata from another trading company, namely, Intraco Trading Pte Ltd, which was subsequently replenished by the TPC whereas in its submissions filed on 27th July, 2012, M/s. Inabata had mentioned that in order to facilitate the urgent request of its customer, it arranged its shipments from common stock available in its warehouse and shipped the goods from its own warehouse up to CIF/ICD, Delhi. Thus, during the interaction on 31st July 2012, it was noted that the goods exported to India during the POI were actually procured from M/s. Intraco Trading Pte. Ltd. It is noted that M/s. Intraco has not cooperated in this investigation at all. Besides, it is also noted that the analysis in this investigation for its final findings was conducted on a month-wise basis and the Authority does not have on record any data as regards the procurement of the subject goods by M/s Intraco from TPC and the SGA expenses etc incurred by it while doing so. M/s Inabata's belated contention that the Authority should ignore these transactions and determine its dumping margin would tantamount to turning a blind eye to all these facts. In the circumstances, the Authority notes that it is not feasible to determine the individual dumping margin for M/s. Inabata.

- As regards, M/s Oman Polypropylene LLC submissions; the Authority notes that the applicant had based its claims on the basis of data obtained from Infodrive India Pvt. Ltd. as the DGCI&S data was not available at that stage. This was considered as *prima facie*

evidence to justify initiation of the investigation in terms of AD Rules. During the course of the investigation, transaction-wise DGC&S data was received and the same was examined by the Authority. The transaction-wise DGC&S data was duly discussed with the counsel of the company to determine their claim of *de-minimis* volume of exports and hence, it is not correct to state that no opportunity was given to them to comment on the same.

- As regards the contention that Oman's Normal Value should be reconstructed in accordance with the Article 2.2.2.1 of the AD Agreement; the Authority notes that relevant extract of Article 2.2.2.1 of the Anti-Dumping Agreement reads as follows:

"Unless already reflected in the cost allocations under this sub-paragraph, costs shall be adjusted appropriately for those non-recurring items of cost which benefit future and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start-up operations."

The Authority had accepted the costs as claimed by the company in Appendix 8 of the exporter's questionnaire response as filed by it in response to the initiation notification and hence it would be wrong to contend that start up costs were not allowed. The on-the-spot-verification report was duly shared with the company, where too there was no mention of the start-up claim made by the company. In response thereto, the company raised no such issue. It is noted that the company had made its claim towards the *lag* end of the investigation, that is, in the 18th month of the investigation; and as the same was an unverified claim, it could not have been accepted by the Authority. In any case, Article 2.2.2.1 of the AD Agreement enjoins the Authorities to take the same on board only if the same have not been reflected in the cost allocations but such an evidence is not on record to show that start-up costs have not been reflected in the cost allocations. The Authority therefore reiterates that it had taken on board the verified data for determination of the Normal value, and the same does not require any change in the Normal value determined. As regards the non-supply of feedstock supply by ORPC, the same also does not require any change in the Normal value determined.

- As regards M/s. Haldia Petrochemicals Ltd. ('HPL') submissions, it is noted that it has endorsed the submissions filed by Reliance Industries Ltd. So far as its contention that in the Preliminary Findings dumping margin was much more than that has been concluded in the final findings; the Authority notes that same is based on wrong appreciation of facts. Antidumping investigation is a process whereby information/data is evaluated as the investigation progresses. Besides, it needs to be noted that considering the facts and merits of the case, it was decided to undertake month-wise analysis in the final determination.
- As regards the contention that injury margin should be disclosed; the Authority notes that the disclosure of the same would lead to the disclosure of the NIP as well, which the interested party has conceded that it could be treated as confidential.
- The Authority examined the issue pertaining to injury and notes that injury analysis has been appropriately undertaken in terms of the AD Rules on the subject and does not warrant any modification in the its final findings of 23rd August 2010. It further notes that

Hon'ble CESTAT vide its order dated 14th May, 2012 has not set-aside the Authority's findings at all but remanded the matter in view ATMA's decision.

- As regards the form of duty; the Authority reiterates that on facts and merits of the case, there is no case to modify the same.
 - As regards the contention regarding the applicability of ATMA's decision is concerned; the Authority notes that the present proceedings are in pursuance of the Hon'ble Tribunal's directions and the interested parties should raise the issue, if any, before the appropriate authority.
 - The Authority finds no merit in the contention that the determination in respect of M/s Marubeni should be revisited. There is no doubt the present findings are recorded in terms of remand directions.
11. After careful examination of the submissions made by interested parties on the subject and considering the legal provisions and facts of the case, the Authority notes that facts on record do not justify nay modification to the final findings dated 23rd August 2010.

Conclusion:

12. Having given opportunity in terms of the orders of Hon'ble CESTAT to interested parties to make oral as well as written submissions, the Authority has examined the same in the paras given above. After having examined the submissions of all the parties, the Authority confirms the conclusions arrived at earlier and indicated in the final findings dated 23rd August 2010.
13. The Authority therefore confirms its earlier recommendation of imposition of the definitive anti-dumping duties on the subject goods originating in or exported from the subject countries, subject to notification No.119 /2010-Customs dated 19th November, 2010 and Notification No.130/2011-Customs dated the 30th December, 2011 issued by the Central Government in this matter. The Authority further recommends that Col.No.6 of Serial No.5 of the duty table of the Final findings dated 23rd August 2010 may be read as 'M/s Advanced Petrochemicals Company' instead of 'Advanced Polypropylene Co.'

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority